वर्ष -चार, अंक -07 अक्टूबर-2024, मूल्यः रू 20

राष्ट्रीय मासिक पत्रिका

नवजीवन संदेश

स्मृति शेष

अनमोल रतन टाटा

RNI No : JHAHIN/2021/83133

CCL

Fuelling Sustainable Growth

हमारा प्रयास : हितधारकों, ग्रामीणों एवं श्रमिकों का सर्वांगीण विकास

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम /कोल इण्डिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कम्पनी)

दरभंगा हाउस, राँची – 834001 (झारखण्ड)

CentralCoalfieldsLtd CCLRanchi centralcoalfieldsltd Central Coalfields Limited

मुईज़ु की भारत यात्रा से क्या बदल गए भारत-मालदीव..

पेज-21

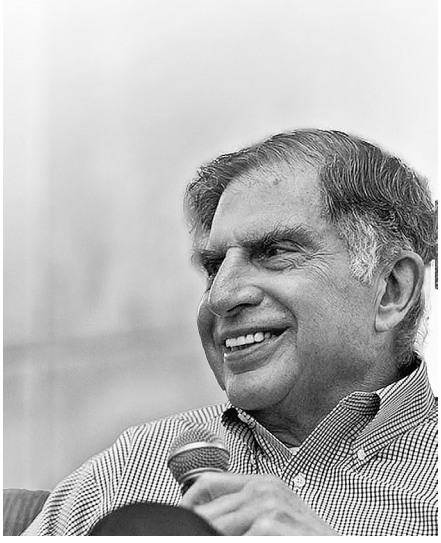

सादगी की मिसाल और दिखावे से दूर रहने वाले ....

पेज-05

अजय जडेजा जामनगर राजघराने के वारिस घोषित; जामसाहब..

पेज-32

index

RNI No: JHAHIN/2021/83133

नवजीवन संदेश

राष्ट्रीय मासिक पत्रिका

Web : navjeewansandesh|com

संबद्धता : प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (भाषा)

▪ वर्ष -4, ▪ अंक -07, ▪ कुल पृष्ठ -36

प्रधान संपादक

पंकज कुमार सिंह

संपादक

प्रभात मजुमदार

संपादकमंडल

जगन्नाथ मुंडा

सुनीता सिन्हा

श्रीमती छाया

रविप्रकाश

खेल डेस्क प्रभारी

चंचल भट्टाचार्य

छायाकार

नसीम अख्तर

संपर्क : 9431708799

9835437102

ईमेलः navjeewansandesh@gmail□com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक और प्रकाशक पंकज कुमार सिंह द्वारा प्रथम तल, होटल आलोका कॉम्प्लेक्स रेडियम रोड, समीप कचहरी चौक, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित तथा मैसर्स डी।,बी। कॉर्प लि। प्लॉट नंबर 535 व 1272, लालगुटवा, पुलिस स्टेशन रातू रांची से मुद्रित।

संपादक : प्रभात मजुमदार* (*संपादक इस अंक में प्रकाशित समाचार के चयन एवं संपादन हेतु पीआरबी एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत उत्तरदायी)

आरएनआई नं।: JHAHIN/2021/83133

संपादकीय

धनी लोगों तक पहुंची साइबर ठगी

देश में साइबर ठगी बहुत आम हो चली है लेकिन एक अरबपति व्यापारी को ठगे जाने का मामला पहली बार सामने आया है. ओसवाल समूह के प्रमुख से करीब सात करोड़ रुपये ठग लिए गए. पुलिस ठगी मामले की जांच कर रही है, जिसमें एक बड़े कपड़ा व्यापारी से लगभग 6.9 करोड़ रुपये की ठगी की गई. ठगों ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट की एक नकली ऑनलाइन सुनवाई में बुलाया और जेल भेजने की धमकी देकर उनसे यह रकम ट्रांसफर करवा ली.

डिजिटल और ऑनलाइन धोखाधड़ी तेजी से बढ़ रही है. पंजाब के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का नाटक कर किसी को ठगना पहले कभी नहीं सुना गया था.

यह मामला तब सामने आया जब पुलिस ने वर्धमान ग्रुप के 82 वर्षीय चेयरमैन एसपी ओसवाल की शिकायत पर दो लोगों को गिरफ्तार किया. ओसवाल ने बताया कि ठगों ने खुद को केंद्रीय जांचकर्ता बताकर उनसे संपर्क किया और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संदिग्ध बताया. उन्होंने एक ऑनलाइन कोर्ट सुनवाई का भी आयोजन किया, जिसमें एक व्यक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ का रूप धारण करके पेश हुआ. इसके बाद उनसे कहा गया कि वे जांच के हिस्से के रूप में अपनी सारी रकम एक खाते में जमा कर दें. ओसवाल ने पुलिस को बताया, "उन्होंने कोर्ट सुनवाई के बारे में स्काइप कॉल की. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, मुझे अपनी सारी रकम एक गोपनीय निगरानी खाते में जमा करने का निर्देश दिया गया."

सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार और चंद्रचूड़ के कार्यालय ने सवालों का जवाब नहीं दिया. ओसवाल ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. पुलिस ने कहा कि उन्होंने आरोपियों से 6 लाख डॉलर (लगभग 5 करोड़ रुपये) बरामद किए हैं, जिसे भारत में इस तरह के मामलों में अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी माना जा रहा है.

ओसवाल के मामले के दस्तावेजों में कहा गया कि उन्हें 'डिजिटल गिरफ्तारी' की धमकी दी गई थी, जो देश में एक बढ़ती हुई समस्या है. यहां ठग वीडियो कॉल पर लोगों से पूछताछ कर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और उनसे ऐसे अपराधों के लिए भुगतान करवाते हैं जो उन्होंने कभी किए ही नहीं होते.

भारत सरकार ने मई में चेतावनी जारी की थी कि 'डिजिटल गिरफ्तारियों' के मामलों की संख्या बढ़ रही है. इन मामलों में साइबर अपराधी कभी-कभी पुलिस की वर्दी पहनकर या पुलिस स्टेशन या सरकारी दफ्तरों जैसे स्टूडियो से काम करते हैं. ऐसे 1,000 से अधिक स्काइप आईडी को ब्लॉक किया गया है.

चेतावनी में गृह मंत्रालय ने कहा था कि संभव है

इसे सीमा पार स्थित आपराधिक गिरोह अंजाम दे रहे हैं. गृह मंत्रालय के मुताबिक ये ठग आमतौर पर संभावित पीड़ित से फोन पर संपर्क करते हैं और कहते हैं कि वे किसी अवैध गतिविधि में शामिल पाए गए हैं. मसलन, उन्होंने कोई पार्सल भेजा है या हासिल किया है, जिसमें अवैध सामान, ड्रग्स, नकली पासपोर्ट या कोई अन्य प्रतिबंधित चीज है. या फिर वे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संदिग्ध हैं.

ऐसे कथित मामले में समझौता करने के लिए पैसे की मांग की जाती है. कुछ मामलों में पीड़ितों को 'डिजिटल अरेस्ट' का सामना करना पड़ता है. कई मामलों में मांग पूरी न होने तक पीड़ित को स्काइप या अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन मौजूद रहने पर मजबूर किया जाता है.

ओसवाल इस प्रकार की ठगी में फंसे सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं. वह पांच दशक पुरानी कपड़ा कंपनी के प्रमुख हैं, जिसका कारोबार 1.1 अरब डॉलर का है और 75 से अधिक देशों में उपस्थिति है.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक 2021 में भारत में साइबर अपराध के कुल 52,974 मामले दर्ज किए गए थे जबकि साल 2022 में ये लगभग 24 फीसदी बढ़कर 65,893 हो गए.

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्र विभाग के शोधकर्ताओं ने इसी साल दुनिया का पहला साइबर क्राइम इंडेक्स जारी किया था जिसमें भारत को खास जगह मिली थी. 'मैपिंग ग्लोबल ज्योग्राफी ऑफ साइबर क्राइम विद द वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स' शीर्षक से जारी एक शोध में विशेषज्ञों ने बताया है कि कहां-कहां साइबर अपराध सबसे ज्यादा हो रहे हैं. इस सूची में 15 देशों के नाम हैं.इंडेक्स में रूस को साइबर क्राइम का सबसे बड़ा गढ़ बताया गया. यूक्रेन इंडेक्स में दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर है. रूस के साथ मिलकर ये दोनों देश साइबर क्राइम के सबसे बड़े अड्डे बताए गए हैं.

शोधकर्ताओं का कहना है कि सूची में शामिल रूस, यूक्रेन, चीन, अमेरिका, रोमानिया और नाइजीरिया ऐसे देश हैं, जो हर तरह के साइबर क्राइम की सूची में टॉप 10 में शामिल हैं. सूची में भारत दसवें नंबर पर है. विशेषज्ञों ने कहा कि भारत में तकनीकी साइबर अपराधों का खतरा तो ज्यादा नहीं है लेकिन वह स्कैम या धोखाधड़ी का केंद्र है. 2022 में अमेरिका ने कहा था कि भारतीय ठगों ने अमेरिकी नागरिकों से आठ खरब रुपये ठगे. सूची कहती है कि दुनिया के 15 देशों से साइबर अपराध होने का खतरा बाकी देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा है लेकिन अन्य देश भी अछूते नहीं हैं.

रतन टाटा

सादगी की मिसाल और दिखावे से दूर रहने वाले शख़्स

रेहान फ़ज़ल

सन 1992 में इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों के बीच एक अद्भुत सर्वेक्षण करवाया गया. उनसे पूछा गया कि दिल्ली से मुंबई की उड़ान के दौरान ऐसा कौन सा यात्री है जिसने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? सबसे अधिक वोट रतन टाटा को मिले. जब इसका कारण ढूंढने की कोशिश की गई तो पता चला कि वो अकेले वीआईपी थे जो अकेले चलते थे. उनके साथ उनका बैग और फ़ाइलें उठाने के लिए कोई असिस्टेंट नहीं होता था. जहाज़ के उड़ान भरते ही वो चुपचाप अपना काम शुरू कर देते थे. उनकी आदत थी कि वो बहुत कम चीनी के साथ एक ब्लैक कॉफ़ी माँगते थे. उन्होंने कभी भी अपनी पसंद की कॉफ़ी न मिलने पर फ़्लाइट अटेंडेंट को डाँटा नहीं था. रतन टाटा की सादगी के अनेक किस्से मशहूर हैं. गिरीश कुबेर टाटा समूह पर चर्चित किताब 'द टाटाज़ हाउ अ फैमिली बिल्ट अ बिजनेस एंड अ नेशन' में लिखते हैं, ''जब वो टाटा संस के प्रमुख बने तो वो जेआरडी के कमरे में नहीं बैठे. उन्होंने अपने बैठने के लिए एक साधारण सा छोटा कमरा बनवाया. जब वो किसी जूनियर ऑफ़िसर से बात कर रहे होते थे और उस दौरान कोई वरिष्ठ अधिकारी आ जाए तो वो उसे इंतज़ार करने के लिए कहते थे. उनके पास दो जर्मन शेफर्ड कुत्ते होते थे 'टीटो' और 'टैंगो' जिन्हें वो बेइंतहा प्यार करते थे. कुत्तों से उनका प्यार इस हद तक था कि जब भी वो अपने दफ़्तर बॉम्बे हाउस पहुंचते थे, सड़क के आवारा कुत्ते उन्हें घेर लेते थे और उनके साथ लिफ़्ट तक जाते थे. इन कुत्तों को अक्सर बॉम्बे हाउस की लॉबी में टहलते देखा जाता था जबकि मनुष्यों को वहाँ प्रवेश की अनुमति तभी दी जाती थी, जब वो स्टाफ के सदस्य हों या उनके पास मिलने की पूर्व अनुमति हो. जब रतन के पूर्व सहायक आर वैंकटरमणन से उनके बॉस से उनकी निकटता के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, "मिस्टर टाटा को बहुत कम लोग करीब से जानते हैं. हाँ दो लोग हैं जो उनके बहुत करीब हैं, 'टीटो' और 'टैंगो', उनके जर्मन शेफर्ड कुत्ते. इनके अलावा कोई उनके आसपास भी नहीं आ सकता.

मशहूर व्यवसायी और लेखक सुहेल सेठ भी एक किस्सा सुनाते हैं, "6 फ़रवरी, 2018 को ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स को बकिंघम पैलेस में रतन टाटा को परोपकारिता के लिए 'रौकफ़ेलर फाउंडेशन लाइफटाइम अचीवमेंट' पुरस्कार देना था. लेकिन समारोह से कुछ घंटे पहले रतन टाटा ने आयोजकों को सूचित किया कि वो वहाँ नहीं आ सकते क्योंकि उनका कुत्ता टीटो अचानक बीमार हो गया है. जब चार्ल्स को ये कहानी बताई गई तो उन्होंने कहा ये असली मर्द की पहचान है. जेआरडी की तरह रतन टाटा को भी उनकी वक्त की पाबंदी के लिए जाना जाता था. वो ठीक साढ़े छह बजे अपना दफ़्तर छोड़ देते थे. वो अक्सर चिढ़ जाते थे अगर कोई दफ़्तर से संबंधित काम के लिए उनसे घर पर संपर्क करता था. वो घर के एकांत में फ़ाइलें और दूसरे काग़ज़ पढ़ा करते थे.

अगर वो मुंबई में होते थे तो वो अपना सप्ताहांत अलीबाग के अपने फार्म हाउस में बिताते थे. उस दौरान उनके साथ कोई नहीं होता था सिवाय उनके कुत्तों के. उनको न तो घूमने का शौक था और न ही भाषण देने का. उनको दिखावे से चिढ़ थी. बचपन में जब परिवार की रोल्स-रॉयस कार उन्हें स्कूल छोड़ती थी तो वो असहज हो जाते थे. रतन टाटा को नज़दीक से जानने वालों का कहना है कि ज़िद्दी स्वभाव रतन की ख़ानदानी विशेषता थी जो उन्हें जेआरडी और अपने पिता नवल टाटा से मिली थी.

जेआरडी की तरह रतन टाटा को भी उनकी वक्त की पाबंदी के लिए जाना जाता था. वो ठीक साढ़े छह बजे अपना दफ़्तर छोड़ देते थे.

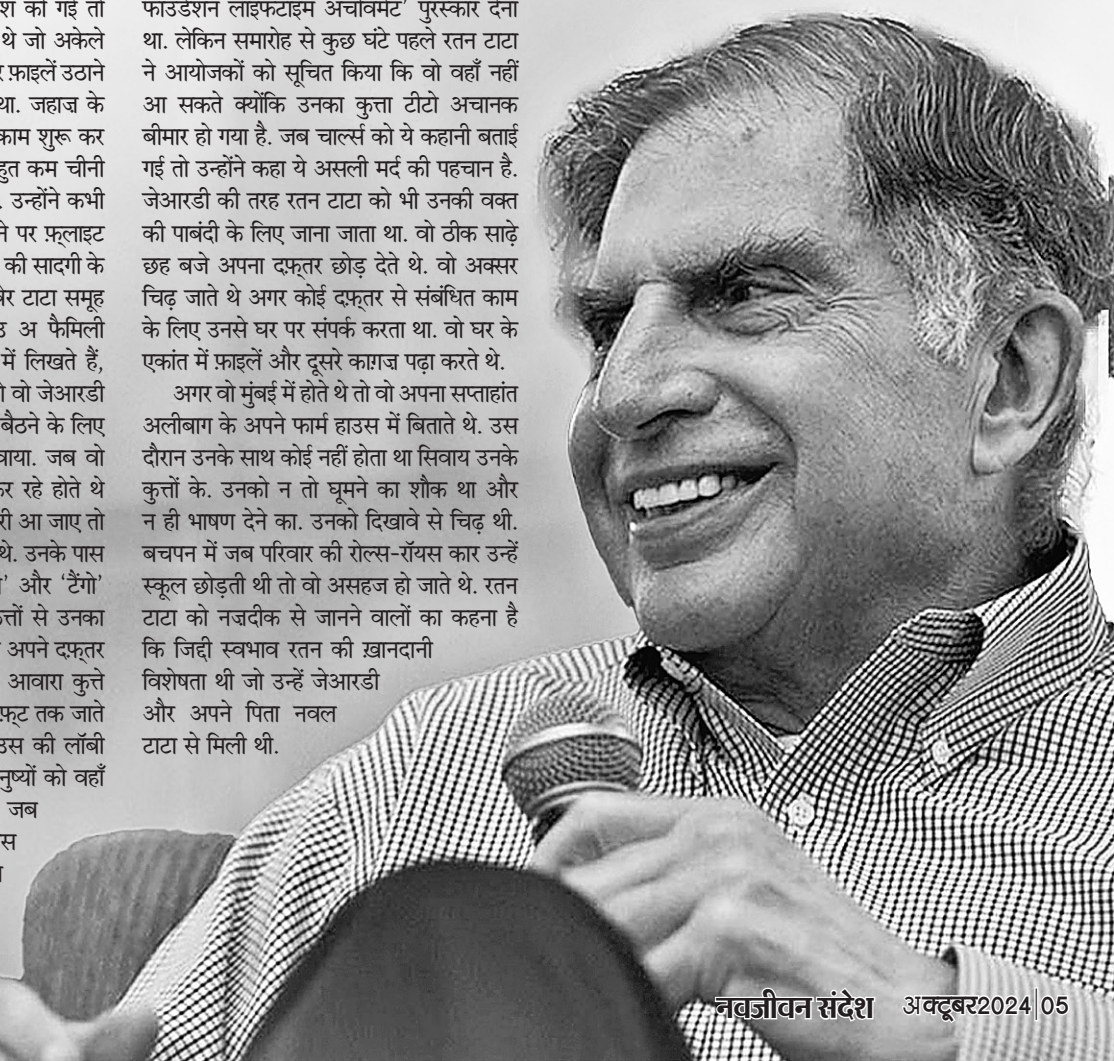

सुहेल सेठ कहते हैं, "अगर आप उनके सिर पर बंदूक भी रख दें, तब भी वो कहेंगे, मुझे गोली मार दो लेकिन मैं रास्ते से नहीं हटूंगा."

अपने पुराने दोस्त के बारे में बॉम्बे डाइंग के प्रमुख नुस्ली वाडिया ने बताया, "रतन एक बहुत ही जटिल चरित्र हैं. मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने उन्हें पूर्ण रूप से जाना है. वो बहुत गहराइयों वाले शख़्स हैं. निकटता होने के बावजूद मेरे और रतन के बीच कभी भी व्यक्तिगत संबंध नहीं रहे. वो बिल्कुल एकाकी हैं. कूमी कपूर अपनी किताब 'एन इंटीमेट हिस्ट्री ऑफ़ पारसीज़' में लिखती हैं, "रतन ने मुझसे खुद स्वीकार किया था कि वो अपनी निजता को बहुत महत्व देते हैं. वो कहते थे शायद मैं बहुत मिलनसार नहीं हूँ, लेकिन असामाजिक भी नहीं हूँ. टाटा की जवानी के उनके एक दोस्त याद करते हैं कि टाटा समूह के अपने शुरुआती दिनों में रतन को अपना सरनेम एक बोझ लगता था. अमेरिका में पढ़ाई के दौरान ज़रूर वो बेफ़िक्र रहते थे क्योंकि उनके सहपाठियों को उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पता नहीं होता था.

रतन टाटा ने कूमी कपूर को दिए इंटरव्यू में स्वीकार किया था, "उन दिनों विदेश में पढ़ने के लिए रिज़र्व बैंक बहुत कम विदेशी मुद्रा इस्तेमाल करने की अनुमति देता था. मेरे पिता क़ानून तोड़ने के हक़ में नहीं थे इसलिए वो मेरे लिए ब्लैक में डॉलर नहीं खरीदते थे. इसलिए अक्सर होता था कि महीना खत्म होने से पहले मेरे सारे पैसे खत्म हो जाते थे. कभी कभी मुझे अपने दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़ते थे. कई बार तो कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए मैंने बर्तन तक धोए. रतन सिर्फ़ 10 साल के थे जब उनके माता-पिता के बीच तलाक हो गया. जब रतन 18 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने एक स्विस महिला सिमोन दुनोयर से शादी कर ली. उधर उनकी माता ने तलाक के बाद सर जमसेतजी जीजीभॉय से विवाह कर लिया. रतन को उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने पाला. रतन अमेरिका में सात साल रहे. वहाँ कॉर्नेल विश्वविद्यालय से उन्होंने स्थापत्य कला और इंजीनियरिंग की डिग्री ली. लॉस एंजिलिस में उनके पास एक अच्छी नौकरी और शानदार घर था. लेकिन उन्हें अपनी दादी और जेआरडी के कहने पर भारत लौटना पड़ा. इस वजह से उनकी अमेरिकी गर्लफ्रेंड के साथ उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका. रतन टाटा ताउम्र अविवाहित रहे.

करियर की शुरुआत

सन 1962 में रतन टाटा ने जमशेदपुर में टाटा स्टील में काम करना शुरू किया. गिरीश कुबेर लिखते हैं, "रतन जमशेदपुर में छह साल तक रहे जहाँ शुरू में उन्होंने एक शॉप फ्लोर मज़दूर की तरह नीला ओवरऑल पहनकर अप्रेंटिसशिप की. इसके बाद उन्हें प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया. इसके बाद वो प्रबंध निदेशक एसके नानावटी के विशेष सहायक हो गए. उनकी कड़ी मेहनत की ख्याति बंबई तक पहुंची और जेआरडी टाटा ने उन्हें बंबई बुला लिया." इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक साल तक काम किया. जेआरडी ने उन्हें बीमार कंपनियों सेंट्रल इंडिया मिल और नेल्को को सुधारने की जिम्मेदारी सौंपी. रतन के नेतृत्व में तीन सालों के अंदर नेल्को (नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स) की काया पलट हो गई और उसने लाभ कमाना शुरू कर दिया. सन 1981 में जेआरडी ने रतन को टाटा इंडस्ट्रीज़ का प्रमुख बना दिया. हालांकि इस कंपनी का टर्नओवर मात्र 60 लाख था लेकिन इस ज़िम्मेदारी का महत्व इसलिए था क्योंकि इससे पहले टाटा खुद सीधे तौर पर इस कंपनी का कामकाज देखते थे.

जीवनशैली

उस जमाने के बिजनेस पत्रकार और रतन के दोस्त उन्हें एक मिलनसार, बिना नख़रे वाले सभ्य और दिलचस्प शख़्स के तौर पर याद करते हैं. कोई भी उनसे मिल सकता था और वो अपना फ़ोन खुद उठाया करते थे.

कूमी कपूर लिखती हैं, "अधिकांश भारतीय अरबपतियों की तुलना में रतन की जीवनशैली बहुत नियंत्रित और सादगी भरी थी. उनके एक बिजनेस सलाहकार ने मुझे बताया था कि वो हैरान थे कि उनके यहाँ सचिवों की भीड़ नहीं थी." "एक बार मैंने उनके घर की घंटी बजाई तो एक छोटे लड़के ने दरवाज़ा खोला. वहाँ कोई वर्दी पहने नौकर और आडंबर नहीं था. कुंबला हिल्स पर मुकेश अंबानी की 27 मंजिला एंटीलिया की चकाचौंध के ठीक विपरीत कोलाबा में समुद्र की तरफ़ देखता हुआ उनका घर उनके अभिजात्यपन और रुचि को दर्शाता है."

जेआरडी ने चुना अपना उत्तराधिकारी

जब जेआरडी 75 साल के हुए तो इस बात की बहुत अटकलें लगाई जाने लगीं कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा. टाटा के जीवनीकार केएम लाला लिखते हैं कि 'जेआरडी... नानी पालखीवाला, रूसी मोदी, शाहरुख़ साबवाला और एचएन सेठना में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बारे में सोच रहे थे. खुद रतन टाटा का मानना था कि इस पद के दो प्रमुख दावेदार पालखीवाला और रूसी मोदी होंगे.' सन 1991 में जेआरडी ने 86 वर्ष की आयु में अध्यक्ष पद छोड़ दिया. इस बिंदु पर उन्होंने रतन का रुख किया. जेआरडी का मानना था रतन के पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी उनका 'टाटा' सरनेम होना. टाटा के दोस्त नुसली वाडिया और उनके सहायक शाहरुख़ साबवाला ने भी रतन के नाम की वकालत की थी. 25 मार्च, 1991 को जब रतन टाटा समूह के अध्यक्ष बने तो उनके सामने सबसे पहली चुनौती थी कि समूह के तीन क्षत्रपों दरबारी सेठ, रूसी मोदी और अजीत केरकर को किस तरह कमजोर किया जाए. ये लोग अब तक टाटा की कंपनियों में प्रधान कार्यालय के हस्तक्षेप के बिना काम करते आए थे.

सन 1991 में जेआरडी ने 86 वर्ष की आयु में अध्यक्ष पद छोड़ दिया. इस बिंदु पर उन्होंने रतन का रुख किया. जेआरडी का मानना था रतन के पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी उनका 'टाटा' सरनेम होना.

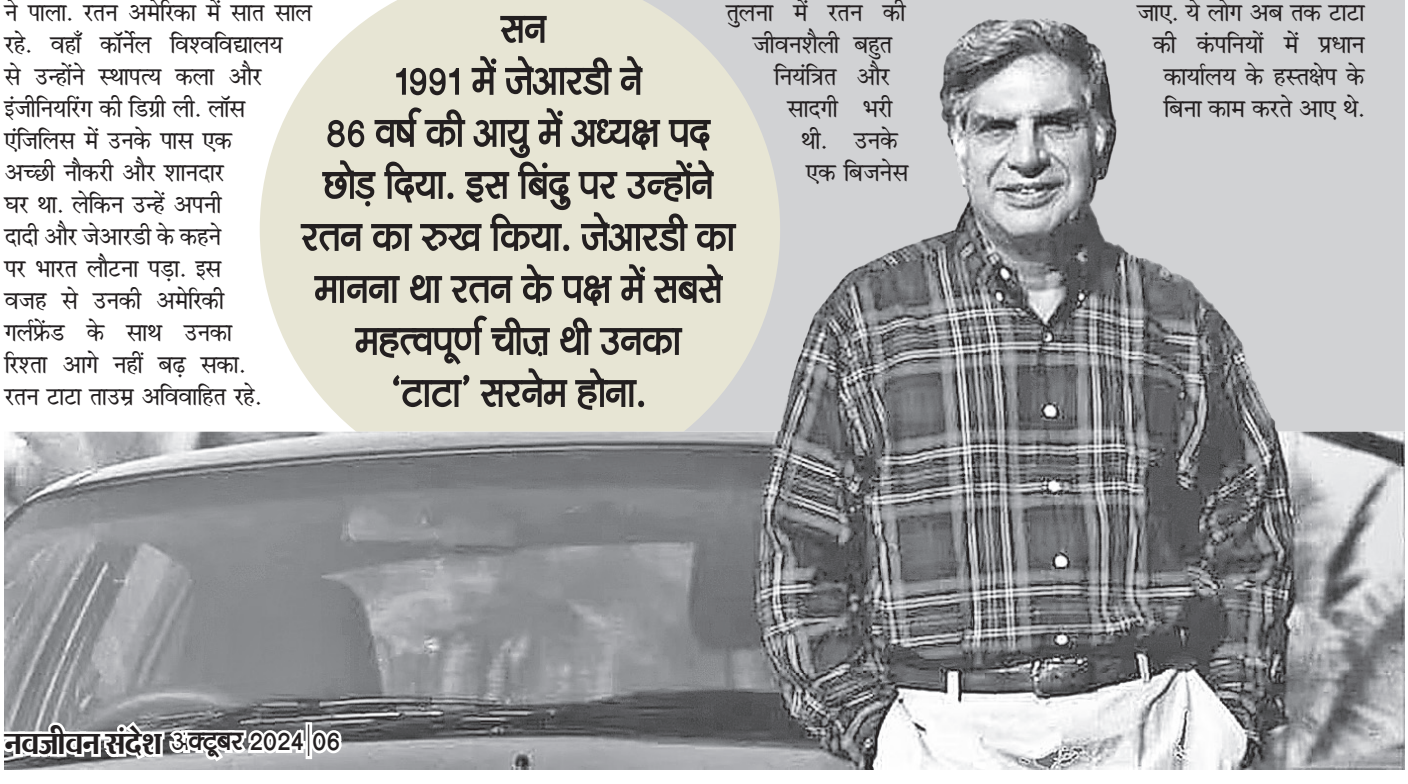

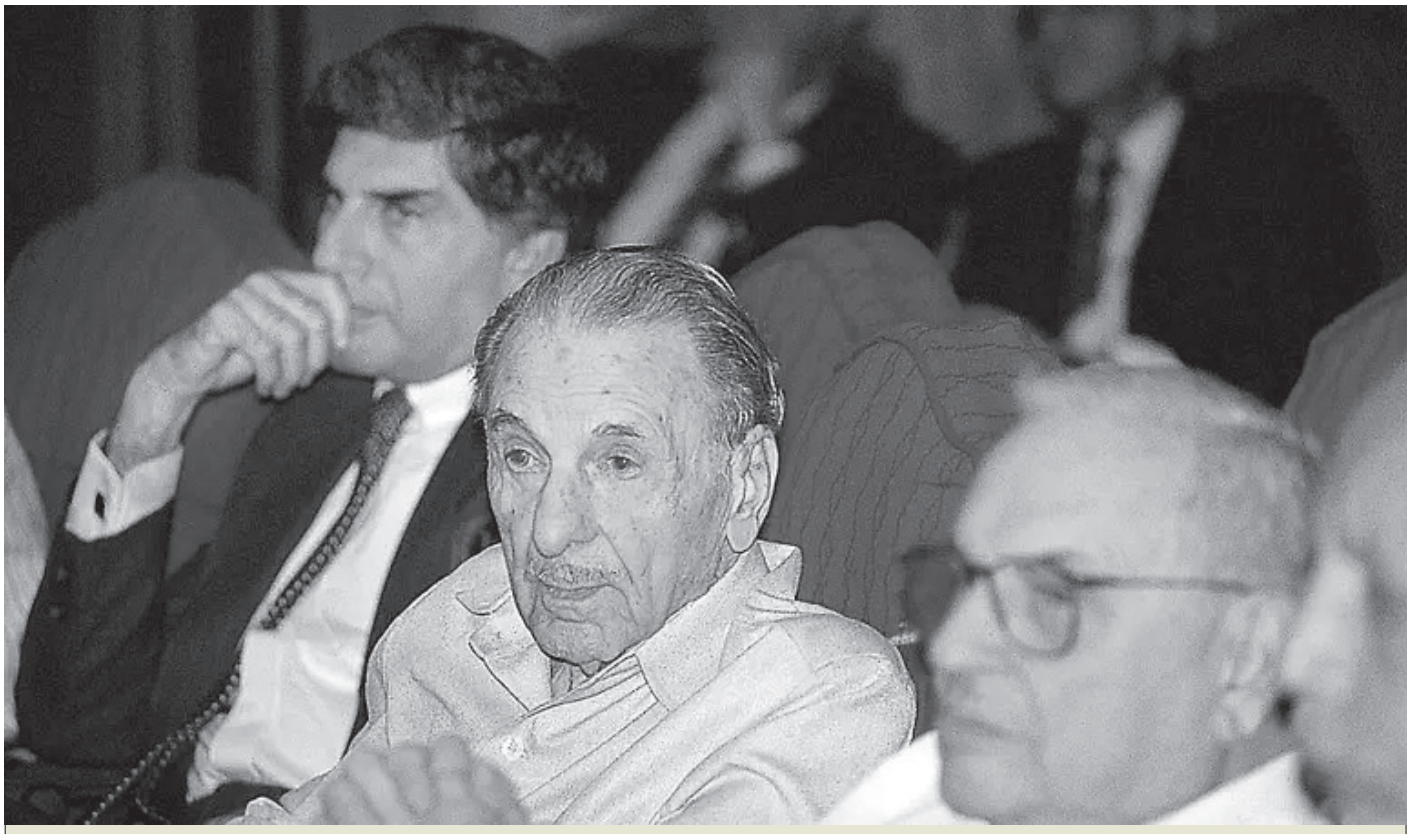

टेटली, कोरस और जेगुआर का अधिग्रहण

शुरू में रतन टाटा की व्यावसायिक समझ पर लोगों ने कई सवाल उठाए. लेकिन सन 2000 में उन्होंने अपने से दोगुने बड़े ब्रिटिश 'टेटली' समूह का अधिग्रहण कर लोगों को चकित कर दिया. आज टाटा की ग्लोबल बेवेरेजेस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी है. इसके बाद उन्होंने यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी इस्पात निर्माता कंपनी 'कोरस' को खरीदा. आलोचकों ने इस सौदे की समझदारी पर सवाल उठाए लेकिन टाटा समूह ने इस कंपनी को लेकर एक तरह से अपनी क्षमता का प्रमाण दिया. सन 2009 के दिल्ली ऑटो एक्सपो में उन्होंने पीपुल्स कार 'नैनो' का अनावरण किया जो एक लाख रुपए की कीमत पर उपलब्ध थी. नैनो से पहले 1998 में टाटा मोटर्स ने 'इंडिका' कार बाजार में उतारी थी जो भारत में डिजाइन की गई पहली कार थी. शुरू में ये कार असफल रही और रतन ने इसे फोर्ड मोटर कंपनी को बेचने का फ़ैसला किया. जब रतन डिट्रॉएट गए तो बिल फोर्ड ने उनसे पूछा कि उन्होंने इस व्यवसाय के बारे में पर्याप्त जानकारी के बिना इस क्षेत्र में क्यों प्रवेश किया? उन्होंने टाटा पर ताना मारा कि अगर वो 'इंडिका' को खरीदते हैं तो वो भारतीय कंपनी पर बड़ा उपकार करेंगे. इस व्यवहार से रतन टाटा की टीम नाराज़ हो गई और बातचीत पूरी किए बिना वहाँ से चली आई. एक दशक बाद हालात बदल गए और 2008 में फोर्ड कंपनी गहरे वित्तीय संकट में फंस गई और उसने ब्रिटिश विलासिता की 'जैगुआर' और 'लैंडरोवर' को बेचने का फ़ैसला किया.

कूमी कपूर लिखती हैं, "तब बिल फ़ोर्ड ने स्वीकार किया कि भारतीय कंपनी फोर्ड की लग्जरी कार कंपनी खरीद कर उस पर बड़ा उपकार करेगी. रतन टाटा ने 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर में इन दोनों नामचीन ब्रांड्स का अधिग्रहण किया."

आलोचना

लेकिन कुछ व्यापार विश्लेषकों ने रतन टाटा की इन बड़ी खरीदारियों पर सवाल भी उठाए. उनका तर्क था कि रतन के कई महंगे विदेशी अधिग्रहण उनके लिए महंगे सौदे साबित हुए. 'टाटा स्टील यूरोप' एक सफेद हाथी साबित हुआ और उसने समूह को भारी कर्ज में डुबोया.

टीएन नैनन ने लिखा, रतन के वैश्विक दाँव अक्खड़पन और खराब समय का मिश्रण थे. एक वित्तीय विश्लेषक ने कहा, 'पिछले दो दशकों में भारतीय व्यापार में सबसे बड़े अवसर दूरसंचार में था, लेकिन रतन ने कम से कम शुरुआत में इसे गँवा दिया.'

मशहूर पत्रकार सुचेता दलाल ने कहा, 'रतन से गलती पर गलती हुई. उनका समूह 'जैगुआर' को खरीदकर वित्तीय बोझ तले दब गया.' लेकिन 'टाटा कंसलटेंसी सर्विस' यानि 'टीसीएस' ने हमेशा टाटा समूह को अग्रणी रखा. इस कंपनी ने वर्ष 2015 में टाटा समूह के शुद्ध लाभ में 60 फीसदी से अधिक का योगदान दिया. सन 2016 में अंबानी की 'रिलायंस' से भी आगे किसी भी भारतीय फर्म का सबसे बड़ा बाज़ार पूंजीकरण इसी कंपनी का था. सन 2010 में रतन टाटा एक बड़े विवाद में फंसे जब लॉबिस्ट नीरा राडिया के साथ उनकी टेलीफोन बातचीत लीक हो गई. अक्तूबर, 2020 में टाटा समूह के अपने ज्वेलरी ब्रांड 'तनिष्क' द्वारा एक विज्ञापन को जल्दबाजी में वापस लिए जाने से भी रतन टाटा की काफी किरकिरी हुई. इस विज्ञापन में सभी धर्मों को बराबर मानने वाले एक समन्वित भारत का मार्मिक चित्रण किया गया था.. इस विज्ञापन को मुखर दक्षिणपंथी ट्रोल्स का सामना करना पड़ा. आखिर 'तनिष्क' को दबाव के चलते वो विज्ञापन वापस लेना पड़ा. कुछ लोगों का मानना था कि अगर जेआरडी जीवित रहते तो वो इस तरह के दबाव में नहीं आते. रतन उस समय भी सवालों के घेरे में आए जब उन्होंने 24 अक्तूबर, 2016 को टाटा समूह के अध्यक्ष साइरस मिस्त्री को एक घंटे से भी कम समय के नोटिस पर बर्खास्त कर दिया.

टाटा को बनाया भरोसेमंद ब्रांड लेकिन इस सब के बावजूद रतन टाटा की गिनती हमेशा भारत के सबसे भरोसेमंद उद्योगपतियों में रही. जब भारत में कोविड महामारी फैली तो रतन टाटा ने तत्काल 500 करोड़ रुपए टाटा न्यास से और 1000 करोड़ रुपए टाटा कंपनियों के माध्यम से महामारी और लॉकडाउन के आर्थिक परिणामों से निपटने के लिए दिए. ख़ुद को गंभीर जोखिम में डालने वालों डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के रहने हेतु अपने लग्जरी होटलों के इस्तेमाल की पेशकश करने वाले पहले शख़्स भी रतन टाटा ही थे. आज भी भारतीय ट्रक चालक अपने वाहनों के पिछले हिस्से पर 'ओके टाटा' लिखवाते हैं ताकि ये पता चल सके कि ये ट्रक टाटा का है, इसलिए भरोसेमंद है. टाटा के पास एक विशाल वैश्विक फुटप्रिंट भी है. ये 'जैगुआर' और 'लैंडरोवर' कारों का निर्माण करता है और 'टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़' दुनिया की नामी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक है. इन सबको बनाने में रतन टाटा की भूमिका को हमेशा याद रखा जाएगा.

भारत के सबसे पुराने कारोबारी समूह के मुखिया रतन टाटा का निधन हो गया। वे टाटा संस के मानद चेयरमैन थे। उन्होंने 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। 7 अक्टूबर को भी उनके अस्पताल जाने की खबर आई थी, लेकिन उन्होंने पोस्ट करके कहा था कि वे ठीक हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा की अगुवाई में ही टाटा ग्रुप ने देश की सबसे सस्ती कार लॉन्च की, तो हाल ही में कर्ज में फंसी एयर इंडिया को 18 हजार करोड़ की कैश डील में खरीदा था। बिजनेस में बेहद कामयाब रतन टाटा निजी जिंदगी में बेहद सादगी पसंद थे और मुंबई में अपने छोटे से फ्लैट में रहते थे।उद्योगपति रतन टाटा का मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वर्ली स्थित श्मशान घाट में उन्हें पंचतत्व में विलीन किया गया। कोलाबा स्थित टाटा के आवास से लेकर राष्ट्रीय प्रदर्शन कला संस्थान और फिर श्मशान घाट तक लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। उनके अंतिम दर्शन के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से लेकर राजनीतिक, कारोबारी, खेल, मनोरंजन जगत के कई बड़े नाम पहुंचे। महाराष्ट्र और झारखंड व गुजरात सरकार ने टाटा के निधन पर एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया।

जन्म

28 दिसंबर 1937

निधन

09 अक्टूबर 2024

रतन टाटा के बाद नोएल टाटा बने टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन

टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन के रूप में नोएल टाटा ने रतन टाटा की जगह ले ली है। नोएल (67) को 'टाटा ट्रस्ट्स' की अगुवाई करने के लिए चुना गया। नोएल टाटा, रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और अब टाटा ट्रस्ट्स का नेतृत्व करेंगे। टाटा ट्रस्ट्स, टाटा सन्स की मालिकाना हक वाली परोपकारी संस्थाएं हैं, जो टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी है। टाटा ट्रस्ट्स की एक शोक सभा आयोजित की गई, जिसके बाद बोर्ड ने नोएल टाटा को रतन टाटा का उत्तराधिकारी नियुक्त करने का फैसला लिया। टाटा संस में 65.9% हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट्स के पास है, 12.87% हिस्सेदारी टाटा ग्रुप की कंपनियों के पास, जबकि 18.4% हिस्सा मिस्त्री परिवार के पास है।

दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले प्रमुख चेहरों में 67 वर्षीय नोएल टाटा अपने बेटे नेविल के साथ नजर आए। भारत के कई शीर्ष नेताओं और उद्योगपतियों ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। रिटेल क्षेत्र में ट्रेंट जैसी बड़ी कंपनी की स्थापना करने वाले नोएल इस दौरान शांत और संयमित दिखे।

नोएल, रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और उनके माता-पिता नवल और सिमोन टाटा हैं। उनकी पत्नी अलू मिस्त्री, पलोनजी मिस्त्री की बेटी और साइरस मिस्त्री की बहन हैं, जिनकी टाटा संस में 18.4% हिस्सेदारी है। नोएल के तीन बच्चे हैं – बेटा नेविल और बेटियां माया व लीआ।

नोएल टाटा ने टाटा समूह में शामिल होने के बाद जून 1999 में रिटेल कारोबार की बागडोर संभाली। साल 2014 में उन्हें पदोन्नत कर इस रिटेल कंपनी का चेयरमैन बनाया गया। वित्त वर्ष 1999 में टाटा समूह के इस रिटेल कारोबार की परिचालन आय 19.7 करोड़ रुपये थी। उस समय वेस्टसाइड ब्रांड इसका हिस्सा था, लेकिन आज ट्रेंट के पास वेस्टसाइड के साथ-साथ लाइफस्टाइल और किराना क्षेत्र के कई प्रमुख ब्रांड भी हैं, जिनमें स्टार बाजार, थोक कारोबार बुकर और सस्ता लाइफस्टाइल ब्रांड जूडियो शामिल हैं।

ट्रेंट ने दुनिया के दो प्रमुख फैशन ब्रांडों – जारा और मासिमो दुती – को भी भारतीय बाजार में पेश किया। पिछले वित्त वर्ष में ट्रेंट की आय 12,669 करोड़ रुपये रही। पहले इसे लैक्मे के नाम से जाना जाता था, जिसे नोएल टाटा की मां सिमोन टाटा ने स्थापित किया था। ट्रेंट का बाजार पूंजीकरण 2,95,704 करोड़ रुपये है। नोएल टाटा ने 2010 से 2021 तक टाटा इंटरनेशनल में काम किया, जो चमड़े के सामान, खनिज और धातुओं का निर्यात करने वाली कंपनी है। अभी वे टाटा समूह की दो कंपनियों – वोल्टास और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं। 2019 में नोएल सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी बने और 2022 में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में शामिल हुए। मई 2023 में उनके तीन बच्चे – लीआ, नेविल और माया – टाटा ट्रस्ट्स की 5 परोपकारी संस्थाओं के बोर्ड में शामिल किए गए। टाटा ट्रस्ट्स टाटा समूह के 150 अरब डॉलर के कारोबार की देखरेख करता है। नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट्स का नया चेयरमैन नियुक्त किए जाने के बाद टाटा समूह की कंपनियों जैसे ट्रेंट, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयरों में मिला-जुला रुझान देखा जा रहा है।

टाटा समूह के शेयरों में हालिया प्रदर्शन के अनुसार, टाटा मोटर्स में 0.23 प्रतिशत की बढ़त रही, टाटा स्टील 0.85 प्रतिशत ऊपर रहा, ट्रेंट में 2.38 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई, जबकि टीसीएस 2.08 प्रतिशत की गिरावट में रहा। रतन टाटा, जो भारतीय व्यवसाय जगत की एक महत्वपूर्ण शख्सियत थे, का 9 अक्टूबर को 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह टाटा सन्स के चेयरमैन एमेरिटस और टाटा ट्रस्ट्स के प्रमुख थे। उन्हें सेहत बिगड़ने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रतन टाटा के निधन से टाटा समूह के परोपकारी कार्यों में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व का खालीपन आ गया है, जिसे अब नोएल टाटा भरने जा रहे हैं।

नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं

महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव, झारखंड में दो चरण में 13 व 20 नवंबर को मतदान

23 नवंबर को मतगणना होगी और नतीजे आएंगे

महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गयी है। महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। वहीं झारखंड में 2 चरण में 13 और 20 नवंबर को मत डाले जाएंगे। दोनों ही राज्यों के चुनाव नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को और झारखंड का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग ने 14 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा भी की।

महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गयी है। महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। वहीं झारखंड में 2 चरण में 13 और 20 नवंबर को मत डाले जाएंगे। दोनों ही राज्यों के चुनाव नतीजे 23 नवंबर को आएंगे।

महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को और झारखंड का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग ने 14 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा भी की।

लोकसभा सीटों में केरल की वायनाड में 13 नवंबर और महाराष्ट्र के नांदेड़ में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं, 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा। सभी के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे।

यहां बता दे कि महाराष्ट्र में महायुति यानी शिवसेना, भाजपा और एनसीपी अजित पवार गुट की सरकार है। एंटी इनकम्बेंसी और 6 बड़ी पार्टियों के बीच बंटने वाले वोट को साधना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी।

2024 लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में इंडिया गठबंधन को 30 और एनडीए को 17 सीटें मिलीं।। इनमें बीजेपी को 9, शिवसेना को 7 और एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिली। भाजपा को 23 सीटों का नुकसान हुआ। 2019 लोकसभा चुनाव से एनडीए को 41 सीटें मिली थीं। 2014 में यह आंकड़ा 42 था। यानी आधे से भी कम।

2024 लोकसभा चुनाव के हिसाब से भाजपा 60 सीटों के आसपास सिमट जाएगी। विपक्षी गठबंधन के एक सर्वे में राज्य की 288 सीटों पर एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी को 160 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। भाजपा के लिए मराठा आंदोलन सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा शिवसेना और एनसीपी में तोड़फोड़ के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ लोगों की सहानभुति है।

झारखंड में महागठबंधन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के नेतृत्व वाली सरकार है। इसमें कांग्रेस, राजद और वाम दल शामिल हैं। भाजपा को झारखंड में सरकार बनाने के लिए संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल की 32 सीटों पर फोकस करना होगा।

संथाल परगना की 18 विधानसभा सीटों में से सिर्फ तीन सीटें अभी भाजपा के पास हैं। पिछले चुनाव में कोल्हान प्रमंडल की 14 विधानसभा सीटों पर तो भाजपा का खाता भी नहीं खुल पाया। जमशेदपुर पूर्वी से तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी हार का सामना करना पड़ा।

जनवरी में भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। हालांकि जमानत मिलने के बाद वे बाहर आए और चंपाई सोरेन से 156 दिन में सीएम का पद वापस ले लिया। इसके बाद चंपाई भाजपा में शामिल हो गए। झारखंड आंदोलन में शिबू सोरेन के साथी रहे चंपाई को कोल्हान टाइगर भी कहा जाता है।

मालूम हो कि 2024 में लोकसभा सहित 6 राज्यों में चुनाव हुए 2024 में लोकसभा के साथ 4 राज्यों- आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा के चुनाव हुए। लोकसभा में भाजपा अकेले बहुमत का आंकड़ा तो पार नहीं कर पाई, लेकिन सहयोगियों के दम पर रिकॉर्ड लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। मोदी पहले गैर कांग्रेसी चेहरे हुए जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने।

वहीं, आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ भाजपा ने सरकार बनाई। चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने। ओडिशा में पहली बार भाजपा ने पूर्ण बहुमत के साथ मोहन चंद्र माझी के नेतृत्व में सरकार बनाई। अरुणाचल में भाजपा ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। सिक्किम में सत्ताधारी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने सरकार बनाई।

हरियाणा में भाजपा 48 सीटें जीतकर रिकॉर्ड तीसरी बार सरकार बनाई है। राज्य में अब तक किसी राजनीतिक दल ने लगातार 3 बार सरकार नहीं बनाई है। जम्मू-कश्मीर में 10 साल बाद हुए चुनाव में जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। कांग्रेस-एनसी गठबंधन ने 48 सीटें हासिल कीं। भाजपा 29 सीटों पर जीती। 15 साल पहले 2009 में भी कांग्रेस और एनसी गठबंधन की सरकार बनी थी। तब उमर 38 साल के थे और राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे।

हरियाणा के चुनावी इतिहास में पहली बार किसी पार्टी ने लगातार तीन विस चुनावों में जीत हासिल की

▪ चंदन कुमार जजवाड़े

हरियाणा राज्य के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी ने लगातार तीन विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की हो. हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी जीत के दावे कर रही थी. राज्य की 90 सीटों के लिए पांच अक्तूबर को वोट डाले गए थे. इन चुनावों में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को कमजोर बताया जा रहा था. बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों में से 48 सीटों पर जीत हासिल की है, जो कि पार्टी के पिछले प्रदर्शन से भी बेहतर है. 2019 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने सिर्फ 40 सीटें हासिल की थीं, जो सरकार बनाने के लिए भी पर्याप्त नहीं थीं. इस बार पार्टी ने 45 के जादुई आंकड़े से तीन सीटें ज्यादा हासिल की हैं.

कांग्रेस ने भी 2019 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन तो किया, लेकिन जीत के लिए जितनी सीटों की जरूरत थी उतनी जुटा नहीं पाई. पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि 2019 में वह सिर्फ 31 सीटें जीत पाई थी. मतदान के बाद लगभग सभी एग्जिट पोलों ने भी कांग्रेस की जीत का अनुमान लगाया था, जो गलत साबित हुए. दो सीटें इंडियन नेशनल लोक दल (आईएनएलडी) ने और तीन सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं.

जानकार भी हरियाणा में बीते 10 साल में बीजेपी की सरकार को लेकर सत्ता विरोधी लहर की बात कर रहे थे और चुनावों में कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे थे. इसके अलावा पांच अक्तूबर को हुई वोटिंग के बाद देश के कई मीडिया संस्थानों ने 'एग्ज़िट पोल' के आधार पर कांग्रेस की जीत के दावे किए थे. एग्जिट पोल में कांग्रेस को न केवल जीतते हुए दिखाया गया था बल्कि 90 सीटों की हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस को क़रीब 60 सीटें मिलने का दावा किया गया था.

हरियाणा में किसानों का मुद्दा हो या 'अग्निवीर' योजना, ऐसे कई मुद्दे थे, जिनकी वजह से बीजेपी सरकार के प्रति लोगों की नाराज़गी बताई जा रही थी. लेकिन विधानसभा चुनावों के नतीजों ने सियासी जानकारों से लेकर एग्जिट पोल तक को गलत साबित किया है.

यही नहीं हरियाणा में अपनी सरकार की वापसी का इंतज़ार कर रही कांग्रेस को इससे बड़ा झटका लगा है. आख़िर वो कौन सी वजहें रही हैं, जिसने राज्य में कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया?

वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री मानते हैं, "इन नतीजों के पीछे सबसे बड़ी वजह रही है बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट. इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हरियाणा में बीजेपी ने ग़ैर जाट वोटों को बड़ी चतुराई से साधा है. इसका असर यह हुआ है कि हुड्डा के गढ़ सोनीपत की पाँच में से चार सीटों पर कांग्रेस की हार हो गई."

1. जाट बनाम गैर-जाट

हेमंत अत्री के मुताबिक़ कांग्रेस की हवा ऐसी थी कि हर जगह उसकी जीत नजर आ रही थी. चाहे वो हरियाणा के विशेषज्ञ हों, आम लोग हों या एग्जिट पोल. लेकिन बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट ने चुनाव के नतीजे बदल दिए.

हरियाणा की राजनीति पर गहरी नज़र वाले वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल के मुताबिक़ हरियाणा में क़रीब 22 फ़ीसदी जाट वोट हैं जो काफ़ी वोकल हैं यानी खुलकर अपनी बात रखते हैं.

"ग़ैर जाटों को लगा कि कांग्रेस के जीतने पर भूपिंदर सिंह हुड्डा ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे इसलिए उन्होंने ख़ामोशी से बीजेपी के पक्ष में वोटिंग कर दी है." आदेश रावल के मुताबिक़ हरियाणा में इस बार के विधानसभा चुनावों में वोटों का बँटवारा जाट और ग़ैर जाट के आधार पर हो गया, जिसका सीधा नुकसान कांग्रेस को हुआ है.

ग़ैर जाट और जाट वोटों के बीच समीकरण साधने में बीजेपी कई सीटों पर कामयाब रही. राज्य की कई सीटों पर उसने करीबी मुकाबले में कांग्रेस को मात दी है. इनमें आसंध, दादरी, यमुनानगर, सफीदों, समलखा, गोहाना, राई, फ़तेहाबाद, तोशाम, बाढड़ा, महेंद्रगढ़ और बरवाला जैसी सीटें शामिल हैं, जहां कांग्रेस को काफी करीबी अंतर से हार का सामना करना पड़ा है.

2. गुटबाजी

हरियाणा में कांग्रेस की हार के पीछे पार्टी के अंदर की गुटबाजी भी एक बड़ी वजह मानी जाती है. जानकार मानते हैं कि राज्य में कांग्रेस के उम्मीदवारों को इस तरह से भी देखा जा रहा था कि कौन भूपिंदर सिंह हुड्डा के खेमे से है और कौन कुमारी शैलजा के क़रीबी है. यही नहीं कांग्रेस के कई उम्मीदवारों को आलाकमान यानी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का उम्मीदवार बताया जा रहा था.

हेमंत अत्री मानते हैं कि हरियाणा में गुटबाज़ी और ग़लत तरीके से टिकट बाँटने की वजह से कांग्रेस को क़रीब 13 सीटें गंवानी पड़ी हैं. इनमें भूपिंदर सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और कांग्रेस आलाकमान की पसंद के उम्मीदवार भी शामिल हैं.

इस मामले में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा को लेकर भी कई तरह की चर्चा चलती रही. यहां तक कहा जाने लगा कि कांग्रेस के कई नेताओं का

ध्यान चुनावों से ज्यादा, चुनाव जीतने के पहले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर था.

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इन चुनावों का सबसे बड़ा सबक यही है कि अति आत्मविश्वास कभी नहीं करना चाहिए. ज़ाहिर है, उनका निशाना कांग्रेस पर ही था.

हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की बात चल रही थी लेकिन दोनों के बीच सीटों की साझेदारी पर सहमति नहीं बन पाई थी.

3. सीटों का बंटवारा

बीजेपी ने इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए थे.

इनमें 16 उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली. बीजेपी अपनी पुरानी 27 सीटें बचा पाने में भी कामयाब रही है जबकि उसके क़रीब 22 नई सीटों पर जीत हासिल की है.

हेमंत अत्री बताते हैं, "कांग्रेस ने अपने किसी विधायक का टिकट नहीं काटा और उसके आधे उम्मीदवारों की हार भी हो गई. उम्मीदवारों को नहीं बदलना भी कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान साबित हुआ है."

साल 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और उसे 40 सीटों पर जीत मिली थी. इस बार बीजेपी ने 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. कांग्रेस को 2019 में 90 में 31 सीटों पर जीत मिली थी. इस साल हुए लोकसभा चुनावों में हरियाणा में कांग्रेस को 43 फ़ीसदी वोट मिले थे जबकि बीजेपी ने 46 फ़ीसदी वोट मिले थे. यानी दोनों प्रमुख दलों के बीच वोटों का अंतर काफी कम रहा था.

4. दलित वोटरों की कांग्रेस से दूरी

लोकसभा चुनावों में बीजेपी को राज्य की क़रीब 44 विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा वोट मिले थे जबकि कांग्रेस 42 विधानसभा क्षेत्रों में आगे रही थी. इस लिहाज़ से भी दोनों दलों के बीच अंतर काफी छोटा रहा था.

जानकारों के मुताबिक लोकसभा चुनावों में दलित वोटों का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के खाते में गया था लेकिन मौजूदा विधानसभा चुनाव में यह वोट कांग्रेस से दूर जाता दिखा है. इस साल के लोकसभा चुनावों में मायावती की बीएसपी को हरियाणा में महज एक फ़ीसदी के करीब वोट मिले थे. मौजूदा विधानसभा चुनाव में उसने राज्य में अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की है.

यही नहीं पिछले विधानसभा चुनावों के मुकाबले इस बार राज्य में आम आदमी पार्टी ने भी राज्य में अपने वोट बैंक में करीब एक फीसदी का इज़ाफ़ा कर लिया है. मसलन राज्य की आसंध विधानसभा सीट पर गिनती खत्म होने के बाद बीजेपी के उम्मीदवार को कांग्रेस से क़रीब 2300 से ज़्यादा वोट मिले हैं जबकि इस सीट पर बीएसपी को 27 हज़ार से ज़्यादा वोट मिले हैं. इस सीट पर आधिकारिक परिणाम की घोषणा अभी बाक़ी है.

बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट

हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो 10 से ज़्यादा सीटों पर छोटे दल या निर्दलीय उम्मीदवार कांग्रेस की हार के पीछे बड़ी वजह रहे हैं. आम आदमी पार्टी हरियाणा में कोई चमत्कार नहीं कर पाई है और न ही उसे किसी सीट पर जीत मिली है. लेकिन छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच वोट बंटने का कांग्रेस को स्पष्ट नुकसान दिखता है. हेमंत अत्री के मुताबिक़ बीजेपी ने उन सभी सीटों पर कांग्रेस विरोधी उम्मीदवार की मदद की, जहाँ उसकी जीत की संभावना कम थी और कांग्रेस की जीत भी स्पष्ट नहीं दिख रही थी. मसलन दादरी विधानसभा सीट को बीजेपी महज 1957 वोट से कांग्रेस से जीत पाई और इस सीट पर तीसरे नंबर पर रहे निर्दलीय संजय छापरिया को 3713 वोट मिले हैं. इसके अलावा भी दो उम्मीदवारों को इस जीत के अंतर से ज़्यादा वोट मिले हैं. यही हाल सफीदों सीट का रहा है. कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी की जीत का अंतर क़रीब 4000 वोट का रहा है, जबकि तीसरे नंबर पर रहे निर्दलीय उम्मीदवार को 20 हज़ार से ज़्यादा वोट मिले हैं. वहीं फतेहाबाद सीट पर बीजेपी को कांग्रेस से महज 2252 ज़्यादा वोट मिले जबकि इस सीट पर अन्य चार उम्मीदवारों को ढ़ाई हज़ार से लेकर क़रीब 10 हज़ार वोट मिले हैं.

आदेश रावल बताते हैं, "इसी साल हुए लोकसभा चुनावों में हरियाणा में दलितों ने कांग्रेस को वोट दिया था. कांग्रेस को सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि तीन महीने में ही दलित वोट उससे दूर हो गए."

उमर अब्दुल्लाः लोकसभा चुनावों में हार के बाद जबरदस्त वापसी

▪ दिलनवाज़ पाशा

जम्मू-कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक परिवार से आने वाले 54 साल के उमर अब्दुल्ला दूसरी बार जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. पहली बार वे साल 2009 में मुख्यमंत्री बने थे. जम्मू-कश्मीर में दस साल के अंतराल के बाद चुनाव हुए हैं और इसके विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हुए भी पांच साल हो चुके हैं.

जीत के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, "2018 के बाद एक लोकतांत्रिक सेटअप जम्मू-कश्मीर का चार्ज लेगा. बीजेपी ने कश्मीर की पार्टियों को निशाने पर लिया, खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को. हमें कमजोर करने की कोशिश की गई.

जम्मू-कश्मीर विधानसभा के नतीजे स्पष्ट होते ही जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ही जम्मू-कश्मीर के नए मुख्यमंत्री होंगे.

जम्मू-कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक परिवार से आने वाले 54 साल के उमर अब्दुल्ला दूसरी बार जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. पहली बार वे साल 2009 में मुख्यमंत्री बने थे. जम्मू-कश्मीर में दस साल के अंतराल के बाद चुनाव हुए हैं और इसके विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हुए भी पांच साल हो चुके हैं.

जीत के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, "2018 के बाद एक लोकतांत्रिक सेटअप जम्मू-कश्मीर का चार्ज लेगा. बीजेपी ने कश्मीर की पार्टियों को निशाने पर लिया, खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को. हमें कमजोर करने की कोशिश की गई. हमारे खिलाफ पार्टियों को खड़ा करने का भी प्रयास हुआ लेकिन इन चुनावों ने उन सब कोशिशों को मिटा दिया है."

उमर अब्दुल्ला इस साल हुए लोकसभा चुनावों में बारामुला से उम्मीदवार थे लेकिन वो उस समय तिहाड़ जेल से चुनाव लड़ रहे इंजीनियर रशीद से चुनाव हार गए थे.

राज्य को संविधान के तहत विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पांच अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया था. जम्मू-कश्मीर अब पूर्ण राज्य नहीं है बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख इस क्षेत्र से अलग हो चुका है.

जम्मू-कश्मीर की सरकार भी अब बहुत हद तक उपराज्यपाल के ज़रिए केंद्र सरकार के नियंत्रण में होगी और मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला के पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं होगा.

हालांकि विश्लेषक ये मान रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ये संदेश देने में कामयाब रहे हैं कि कश्मीर के लोग अब भी उन पर विश्वास कर रहे हैं. लेकिन इस साल जुलाई तक अब्दुल्लाह कह रहे थे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि जम्मू-कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है. उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से कहा था, "मैं एक पूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं. मैं खुद को ऐसी स्थिति में नहीं देख सकता जहां मुझे उपराज्यपाल से चपरासी चुनने के लिए कहना पड़े या बाहर बैठकर फाइल पर उनके हस्ताक्षर करने का इंतजार करना पड़े."

शोधकर्ता और लेखक मोहम्मद यूसुफ़ टेंग मानते हैं कि ये कश्मीर के लिए अहम पड़ाव है और इन चुनावों ने ये संदेश दिया है कि कश्मीर की पहचान से समझौता नहीं किया जा सकता है और यही कश्मीर के लोगों के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा है.

टेंग कहते हैं, ''उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कांफ्रेंस के चुनाव अभियान का नेतृत्व किया और वो अपनी ये बात समझाने में कामयाब रहे कि दिल्ली ने किस तरह से कश्मीरियत का नुकसान किया और कश्मीर के लोगों की उम्मीदों को किस तरह से कुचला.'' उनके मुताबिक उमर अब्दुल्ला लोगों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहे और कश्मीर के लोगों ने उन्हें अपना नेता मान लिया

है. टेंग कहते हैं कि कश्मीर के लोगों ने ये बताया है कि उनके पास जो मताधिकार है, वो उसका अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करेंगे.

हालांकि कश्मीर के बदले राजनीतिक हालात में,अब जो मुख्यमंत्री होगा उसके पास बहुत सीमित राजनीतिक ताक़त ही होगी. विश्लेषक मान रहे हैं कि राजनीतिक रूप से भले ही उमर अब्दुल्ला बहुत ताकतवर न रहें लेकिन फिर भी प्रतीकात्मक रूप से उनकी पार्टी की ये जीत बहुत अहम है.

अब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू-कश्मीर में उप-राज्यपाल का पद बहुत ताकतवर है, मुख्यमंत्री को उसके मातहत ही काम करना होगा, लेकिन बावजूद इसके, उमर अब्दुल्ला ये संदेश देने में तो कामयाब ही रहे हैं कि कश्मीर की जनता की पसंद वो ही हैं.

टेंग कहते हैं, ''उमर अब्दुल्ला के अपने हाथ में क्या होगा, वो एक क्षेत्रीय नेता हैं, लेकिन कश्मीर में सरकार दिल्ली से चल रही है. अगर जम्मू-कश्मीर में एक मामूली ट्रांसफर भी करना होगा,उमर अब्दुल्ला नहीं कर पाएंगे. बावजूद इसके, वो कश्मीर के लोगों के नेता हैं और यहां की जनता की उम्मीदों का बोझ उन पर ही होगा.'' चुनाव अभियान के दौरान जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कई वादे किए थे. इनमें सबसे अहम वादा कश्मीर के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना और रोजगार के बेहतर मौके पैदा करना है.

पिछले पांच साल से उपराज्यपाल के दफ्तर से कश्मीर में प्रशासन चल रहा है. आम लोगों ने अपने आप को सत्ता से दूर महसूस किया. टेंग कहते हैं, '' उमर के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो लोगों को ये अहसास करा पाएं कि अब सत्ता और शासन उनके क़रीब है.''

उमर अब्दुल्ला का जन्म 10 मार्च 1970 को न्यूयॉर्क के रोचेस्टर में हुआ था. उनके परिवार के पास जम्मू-कश्मीर में लंबी राजनीतिक विरासत है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दोबारा दिलाने के लिए जद्दोजहद करने का वादा भी किया है. इन वादों को पूरा करने का बोझ भी उमर अब्दुल्ला के कंधों पर ही होगा.

उमर अब्दुल्ला का जन्म 10 मार्च 1970 को न्यूयॉर्क के रोचेस्टर में हुआ था. उनके परिवार के पास जम्मू-कश्मीर में लंबी राजनीतिक विरासत है. उमर के दादा शेख अब्दुल्ला प्रमुख कश्मीरी नेता और राज्य के पहले प्रधानमंत्री थे. उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के बर्न हॉल स्कूल से शुरुआती शिक्षा ली और फिर मुंबई की सिडेनहैम कॉलेज से कॉमर्स में स्नातक की डिग्री हासिल की. परिवार के राजनीतिक इतिहास को देखते हुए राजनीति में उमर का आना स्वाभाविक ही था.

उमर अब्दुल्ला ने साल 1998 में श्रीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और 28 साल की उम्र में संसद पहुंच गए. उमर अब्दुल्ला देश के सबसे युवा सांसदों में से एक थे. वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में राज्य मंत्री भी रहे. इसके अगले साल ही वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की यूथ विंग के अध्यक्ष बन गए और उन्हें सिर्फ़ अपनी पार्टी के भीतर ही नहीं बल्कि देश में भी पहचान मिली. इसके ठीक दस साल बाद, साल 2009 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई तब युवा उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने. अपने पहले मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान उमर अब्दुल्ला ने शिक्षा, ढांचागत विकास और स्वास्थ्य सेवाएं विकसित करने पर ज़ोर दिया. उन्होंने कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए.

लेकिन उमर अब्दुल्ला के लिए सब कुछ आसान नहीं था. भारतीय संसद पर हमले के अभियुक्त अफजल गुरु को फांसी दिए जाने और साल 2010 में जम्मू-कश्मीर में पैदा हुए तनावपूर्ण हालात ने उनके सामने मुश्किल चुनौतियां पेश की. 2010 में कश्मीर में फिर से उठे अलगाववाद से निपटने में भी वो बहुत कामयाब नहीं रहे और इसका खामियाजा उन्हें अगले चुनावों में भुगतने को मिला.

2014 विधानसभा चुनावों में पार्टी की बुरी हार के बावजूद वो नेशनल कांफ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे. 2019 में जब केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया और अनुच्छेद 370 को हटा दिया तो वो सरकार के इस फैसले के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक आवाज़ बनकर उभरे.

उमर अब्दुल्ला लंबे समय तक नजरबंद भी रहे. बावजूद इसके, वो ये संदेश देते रहे कि कश्मीर के लोग विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और इसका विरोध जारी रखेंगे. अब एक बार फिर सत्ता की कमान उनके हाथ में होगी, लेकिन इस बार उनके सामने सिर्फ़ हालात ही अलग नहीं होंगे बल्कि चुनौतियां भी नई होगी.

कोयला एवं खान मंत्री ने सीसीएल के दो परियोजनाओं का किया शिलान्यास

कोयला एवं खान राज्य मंत्री , भारत सरकार,सतीश चंद्र दुबे ने पिछले दिनों सीसीएल के बोकारो एवं करगली क्षेत्र में कारो कोल हैंडलिंग प्लांट एवं कोनार कोल हैंडलिंग प्लांट का शिलान्यास किया।। इन दोनों परियोजनाओं की क्षमता क्रमशः 7 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष है।

फर्स्ट माइल रेल कनेक्टिविटी की दिशा में ये दोनों कोल हैंडलिंग प्लांट एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा जिसके तहत कोयला खदानों से उत्पादित कोयले को निकटतम रेलवे सर्किट तक ले जाने की व्यवस्था की जायेगी, जहां से इसे देश भर के ताप विद्युत संयंत्रों तथा अन्य उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। वर्तमान में, इन खानों से कोयला टिपर द्वारा सड़क मार्ग से रेलवे साइडिंग तक लाया जाता है।

---कोनार कोल हैंडलिंग प्लांटः इस संयंत्र में रिसीविंग हॉपर, क्रशर, 10000 टन क्षमता के कोयला भंडारण बंकर और 1.6 किमी लंबा कन्वेयर बेल्ट सम्मिलित हैं, जिनकी सहायता से कोयले को 1000 टन भंडारण क्षमता के साइलो बंकर द्वारा रेलवे वैगनों में स्थानांतरित किया जाएगा। 5 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता की इस परियोजना की लागत 322 करोड़ है।इसके परियोजना के प्रारंभ होने से वर्तमान रैक लोडिंग समय 5 घंटे से घटकर 1 घंटा हो जाएगा। जिसे कोयल प्रेषण में तेजी आएगी और रेक़ की उपलब्धता बढ़ेगी।

ये एक क्लोज्ड-लूप, पूर्ण यंत्रीकृत प्रणाली है जो सड़क द्वारा परिवहन को समाप्त करके कोयले के प्रेषण में तेजी और दक्षता लाएगी और इस प्रकार से डीजल की खपत न्यूनीकृत करेगी। इस परियोजना के आरंभ होने पर धूल और वाहन जनित प्रदूषण कम होगा, जिससे क्षेत्र के पर्यावरण में गुणात्मक सुधार होगा।

ज्ञात हो कि सीएमडी सीसीएल निलेंदु कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम सीसीएल कई नई परियोजनाओं की शुरुआत कर रहा है,जिससे कोयला उत्पादन एवं प्रेषण में वृद्धि आएगी।

अवसर विशेष पर सांसद ,गिरिडीह,चंद्र प्रकाश चौधरी , धायक,बेरमो, कुमार जयमंगल (अनूप सिंह) ,कोल इंडिया के अध्यक्ष पीएम प्रसाद,सीएमडी सीसीएल निलेंदु कुमार सिंह, निदेशक (वित्त) पवन कुमार मिश्रा, निदेशक (कार्मिक) हर्ष नाथ मिश्र, निदेशक तकनीकी (संचालन)श्री हरीश दुहान, निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) श्री सतीश झा एवं श्रमिक संघों के प्रतिनिधि गण,महाप्रबंधक गण , विभागाध्यक्ष गण सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। मंत्री श्री दुबे ने कोनार परियोजना के शिलान्यास के क्रम में पौधारोपण भी किया।

कारो कोल हैंडलिंग प्लांट

इस संयंत्र में रिसीविंग हॉपर, क्रशर, 15000 टन क्षमता के कोयला भंडारण बंकर और 1 किमी लंबा कन्वेयर बेल्ट सम्मिलित हैं, जिनकी सहायता से कोयले को 4000 टन भंडारण क्षमता के साइलो बंकर द्वारा रेलवे वैगनों में स्थानांतरित किया जाएगा। 7 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता की इस परियोजना की लागत 410 करोड़ है।इसके परियोजना के प्रारंभ होने से वर्तमान रैक लोडिंग समय 5 घंटे से घटकर 1 घंटा हो जाएगा। जिसे कोयल प्रेषण में तेजी आएगी।

बीसीसीएल ने शिविर लगा कर एक साथ 50 लोगों को दिया अनुकंपा नियोजन

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के अध्यक्ष -सह -प्रबंध निदेशक (सीएमडी) समीरन दत्ता के निर्देश और निदेशक कार्मिक की विशेष पहल से बीसीसीएल ने पूजा से पहले एक साथ 50 लोगों के लिए अनुकंपा आधारित नियोजन के लिए शिविर लगा कर उन्हें कंपनी में नियुक्ति दी। कोयला नगर सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 2011 से लेकर 2022 तक के विभिन्न मामलों में अनुकंपा नियोजन और आर्थिक मुआवजा दिया गया। इस शिविर में 48 लाभार्थियों को कंपनी में नियोजन तथा 02 को आर्थिक मुआवजा प्रदान किया। कोल इंडिया गीत और दीप प्रज्ज्वलन के साथ आरंभ हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएमडी श्री समीरन दत्ता ने की और इस अवसर पर निदेशक (कार्मिक) श्री मुरली कृष्ण रमैया, निदेशक (वित्त) श्री राकेश कुमार सहाय और निदेशक तकनीकी (संचालन) श्री संजय कुमार सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। बीसीसीएल में ऐसा पहली बार है कि सीएमडी के साथ निदेशक मंडल ने स्वयं उपस्थित रहकर अपने हाथों से एक साथ इतनी संख्या में लाभार्थियों को नियोजन-पत्र सौंपे।

इस अवसर पर बोलते हुए सीएमडी श्री समीरन दत्ता ने कहा, "हम अनुकंपा नियोजन के माध्यम से बीसीसीएल के अपने पुराने परिवारों को फिर से कंपनी के साथ जोड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि कंपनी के कार्मिक विभाग ने नियोजन के मामलों में तेजी लाते हुए पिछले पांच वर्षों में 2300 मामलों में से

2000 से अधिक मामलों में अनुकंपा नियोजन दे दिया गया है। इस त्वरित समाधान एवं नियोजन के लिए कार्मिक विभाग के सभी अधिकारी बधाई के पात्र हैं। आज के इस शिविर में 2011 से 2022 तक के मामलों को युद्ध स्तर पर शीघ्रता से निपटाकर नियोजन प्रदान किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कंपनी आने वाले सभी नये कार्मिकों को बीसीसीएल परिवार में स्वागत करते हुए उन्हें पूजा और दीपावली की शुभकामनाएं भी दीं।"

निदेशक कार्मिक श्री मुरली कृष्ण रमैया ने अपने संबोधन में बताया कि आज के अनुकंपा नियोजन शिविर में ब्लॉक II से 01, कतरास से 10, लोदना से 04, सिजुआ से 03, बस्ताकोला से 06, पूर्वी झरिया से 04, कुसुंडा से 07, गोविंदपुर से 06, चाँच विक्टोरिया से 04, पश्चिमी झरिया से 03, वाशरी डिवीजन से 01, बरोरा से 01, सहित कुल 50 मामलों का निपटान किया गया। इस वर्ष अब तक कुल 266 आश्रितों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। इसी प्रकार वर्ष 2023 में 470 , 2022 में 377 और 2021 में 247 आश्रितों को कंपनी में नियोजन प्रदान किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि आज का शिविर 1.0 के नाम से आयोजित किया गया है, शीघ्र ही बीसीसीएल द्वारा अनुकंपा नियोजन शिविर 2.0 का भी आयोजन कर पात्र लोगों को अनुकंपा नियोजन प्रदान किये जाएंगे।

कार्यक्रम का आयोजन श्रमशक्ति एवं नियोजन विभाग द्वारा किया गया जिसमें विभाग के प्रमुख श्री सत्य प्रिय राय ने स्वागत वक्तव्य दिया और उप महाप्रबंधक, औद्योगिक संबंध एवं प्रशासन श्री सुरेन्द्र भूषण ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। इस महाप्रबंधक कार्मिक श्री बिद्युत साहा, महाप्रबंधक कल्याण श्री सरोज पाण्डेय, सभी क्षेत्रों के क्षेत्रीय महाप्रबंधक एवं क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधकों के अलावा बीसीसीएल केन्द्रीय सलाहकार समिति, कल्याण परिषद के सदस्य, विभिन्न श्रमिक संगठनों और सीएमओएआई के प्रतिनिधि और कोयला भवन मुख्यालय के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष भी उपस्थित रहे।

ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ସଶକ୍ତ,
ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ
ଅନୁପ୍ରାଣିତ

ଶୁଭ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା !

ପାର୍ବଣର ଶୁଭ ଅବସର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ
ପ୍ରଗତି, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଭରା ହେଉ।

नालको NALCO

ordinary people, extraordinary attitude

nalcoindia NALCO_India nalco_india nalco_india nalcoindia

सतत विकास के मार्ग पर अग्रसर दामोदर घाटी निगम

"श्री एस. सुरेश कुमार, आईएएस ने 01 जनवरी 2024 से डीवीसी के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। इस पद को संभालने से पूर्व, श्री कुमार महानिदेशक, नेताजी सुभाष प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता के पद पर कार्यरत थे। श्री कुमार 1988 में पश्चिम बंगाल कैडर में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए। उनके पास आईआईटी मद्रास से केमिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक की डिग्री है। श्री एस. सुरेश कुमार ने 0। नवंबर 2019 से अप्रैल 2023 तक पश्चिम बंगाल सरकार के'विद्युत विभाग'में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया है और उन्हें 'गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन विभाग', पश्चिम बंगाल सरकार, का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था। श्री कुमार ने अपने करियर के दौरान कई प्रशासनिक पदों पर भी कार्य कियाः 2006-08 तक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के निदेशक (वित्त) के रूप में, 2009 के दौरान भारत के चुनाव आयोग में ओएसडी के रूप में, 2008-2014 तक गृह मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के रूप में। वह तकनीकी और प्रशासनिक दोनों ही क्षेत्रों में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं।''

दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) की स्थापना 1948 में दामोदर घाटी निगम अधिनियम (1948 के अधिनियम संख्या XIV) के माध्यम से भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और दामोदर नदी के संसाधनों के प्रबंधन के लिए डिज़ाइन की गई एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में की गई थी, जो पूर्वी हिस्से में बहती है। ऐतिहासिक रूप से, इस क्षेत्र को गंभीर बाढ़, सूखा और मिट्टी का कटाव सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था और कृषि उत्पादकता और आर्थिक विकास में काफी बाधा होती थी , जिससे व्यापक गरीबी पैदा हुई। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, डीवीसी को बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए एक व्यापक रणनीति लागू करने का काम सौंपा गया था, जिससे अंततः घाटी में सतत विकास के लिए आधार तैयार हुआ । निगम की प्रारंभिक प्रमुख परियोजनाओं में बांध, बैराज और कोयला आधारित बिजली संयंत्रों का निर्माण शामिल था। तिलैया, पंचेत और मैथन बांध के साथ-साथ बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन और दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं; डीवीसी बांध नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने, बाढ़ के खतरे को काफी कम करने और क्षेत्र के कृषि क्षेत्रों को आवश्यक सिंचाई पानी उपलब्ध कराने में सहायक बन गए। इन पहलों ने न केवल तात्कालिक पर्यावरणीय चिंताओं को कम किया बल्कि विश्वसनीय जल आपूर्ति सुनिश्चित करके भविष्य के औद्योगिक विकास के लिए भी मंच तैयार किया।

आज, डीवीसी एक बहुआयामी संगठन के रूप में खड़ा है, जो बिजली उत्पादन, सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन सहित कई गतिविधियों की देखरेख करता है। 6540 मेगावाट से अधिक उत्पादन क्षमता के साथ, यह भारत में सबसे बड़े बिजली उत्पादकों में से एक है। डीवीसी थर्मल, जलविद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों सहित ऊर्जा उत्पादन सुविधाओं का एक विविध पोर्टफोलियो संचालित करता है। डीवीसी ने 147.2 मेगावाट जल विद्युत और 13.92 मेगावाट सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता स्थापित की है। डीवीसी के पास विभिन्न KV की 8622 Ckm ट्रांसमिशन लाइनों का नेटवर्क हैऔर लगभग 48 सब-स्टेशन हैं । डीवीसी के पास चार डीवीसी जलाशयों के माध्यम से कुल मौजूदा संरक्षण भंडारण क्षमता 870 CMC है। खनन क्षेत्र में डीवीसी के पास 6 मिलियन टन का PRC है जो उत्पादन के पांचवें वर्ष में होगा।

डीवीसी थर्मल पावर प्लांट नियमित रूप से हर महीने केंद्रीय क्षेत्र के शीर्ष 10 उच्चतम PLF संयंत्रों में आ रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 76.81% का औसत PLF हासिल किया गया जो पूरे भारत के औसत PLF से काफी अधिक है। पिछले वित्तीय वर्ष में डीवीसी ने वार्षिक उत्पादन के मामले में 2.27% की वृद्धि देखी। इसके अलावा, पिछले वित्तीय वर्ष में राजस्व संग्रह में 9.5% की वार्षिक वृद्धि हुई थी। डीवीसी के विस्तार के साथ-साथ जनशक्ति में भी विस्तार हो रहा है और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान जनशक्ति में 5.35% की वृद्धि हुई थी।

हाल के वर्षों में, डीवीसी ने जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने और अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने की तत्काल आवश्यकता को पहचाना है। निगम ने सौर और जलविद्युत दोनों परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। वर्ष 2030 तक कुल सौर ऊर्जा क्षमता 3433 मेगावाट करने का लक्ष्य है और पम्पेडस्टोरेज में 2500 मेगावाट का लक्ष्य है. कुल मिला के नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 33% बढ़ाने का उद्देश्य है.

डीवीसी पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए हर कदम उठा रहा है और पहले से ही फ़्लू गैस डिसल्फराइजेशन सिस्टम की छह इकाइयां चालू कर चुका है। थर्मल ऊर्जा का भी विस्तार कर के 2030 तक 11060 मेगावाट करने का लक्ष्य है.

आगे देखते हुए, दामोदर घाटी निगम का भविष्य आधुनिकीकरण, नवाचार और विस्तार पर केंद्रित है। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन पर भारत सरकार का जोर डीवीसी के रणनीतिक उद्देश्यों के साथ निकटता से मेल खाता है। सौर, पनबिजली और थर्मल में क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य के साथ, निगम सक्रिय रूप से अपने ऊर्जा पोर्टफोलियो का विस्तार करने की योजना पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
HINDUSTAN COPPER LIMITED
Schedule "A" CPSE under Ministry of Mines, Govt. of India

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को

श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण

के लिए तांबा उपलब्ध कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है

एचसीएल ने मंदिर निर्माण में

पत्थर के स्लैब को

एक-दूसरे से जोड़ने के लिए

तांबे की स्ट्रिप्स और तार की छड़ें प्रदान की हैं,
दोनों **99.99% शुद्ध इलेक्ट्रो-रिफाइंड तांबा हैं।**
उच्चतम गुणवत्ता वाला तांबा सुदीर्घता सुनिश्चित करता है
और इस प्रकार चट्टान के जोड़ों को हजारों वर्षों तक कायम रखेगा।

देश का ताम्र खनिक

मुईजु की भारत यात्रा से क्या बदल गए भारत-मालदीव रिश्ते

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुईजू भारत के पांच दिवसीय दौरे पर आए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत के बाद कई घोषणाएं की गईं, लेकिन यात्रा के सभी उद्देश्य किस सीमा तक पूरे हो पाए हैं, यह कहना मुश्किल है. मुईजू के दिल्ली आने पर उनका स्वागत विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने किया. राष्ट्रपति भवन में उनका और उनकी पत्नी सजिदा मुहम्मद का औपचारिक स्वागत किया गया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोगों ने उनसे मुलाकात की.

हालांकि स्वागत के दौरान मोदी ने मुईजु को गले नहीं लगाया, सिर्फ उनसे हाथ मिलाए. मोदी दुनियाभर के नेताओं को मिल कर गले लगाने के लिए जाने जाते रहे हैं. नई दिल्ली में स्थित हैदराबाद हाउस में मोदी और मुईजु के नेतृत्व में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद दोनों नेताओं ने मीडिया के सामने बयान दिए. मोदी ने कहा कि भारत मालदीव के लिए संकट के समय "फर्स्ट रेस्पॉन्डर" यानी सबसे पहले मदद देने वाला देश रहा है, चाहे वो संकट पीने के पानी का रहा हो या कोविड का टीके का.

मुईजु ने अपने बयान में कहा, "मालदीव हमारे देशों और हमारे इलाके की शांति और विकास के लिए प्रतिबद्ध एक मित्र बना रहेगा." दोनों देशों के बीच कई तरह की सहयोग परियोजनाओं की घोषणा की गई. बताया गया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार संधि (एफटीए) पर चर्चा शुरू कर दी गई है. इसके अलावा बेंगलुरु में मालदीव का वाणिज्यिक दूतावास और मालदीव के अद्दू में भारत का वाणिज्यिक दूतावास खोलने पर भी चर्चा शुरू की जाएगी. दोनों देशों के रिश्ते नवंबर 2023 में मुईजू के मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद ही बिगड़ने लगे थे. सत्ता संभालने ही उन्होंने "भारत प्रथम" नीति को समाप्त करने का संकल्प लिया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए. मुईजू ने दर्जनों भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने का आदेश भी दिया, जो मालदीव में भारत के कुछ विमानों के रखरखाव के लिए तैनात थे. विमान अभी भी वहीं हैं लेकिन उनके रखरखाव के लिए अब सैनिकों की जगह सिविलियन तैनात हैं.

भारतीय सैनिकों की वापसी के बाद मालदीव ने चीन के साथ एक "सैन्य सहायता" समझौते पर हस्ताक्षर किए. इसके अलावा, मालदीव ने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पर भारत के साथ 2019 के समझौते को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया. साथ ही, 2024 की शुरुआत में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की, तो मुईजू सरकार के कुछ मंत्रियों ने मोदी और भारत के बारे में अपमानजनक बयान दिए. इसके बाद बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटकों ने मालदीव का बहिष्कार करने की अपील भी की, जिससे मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में काफी गिरावट आई. हालांकि बीते कुछ महीनों से मुईजू सरकार ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने की दिशा में काम करना शुरू किया है. इसी साल मई में मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत आए थे और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की थी. फिर जून में लोकसभा चुनावों के बाद मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए जिन देशों के नेताओं को निमंत्रण दिया गया, उनमें मुईजू भी थे. इस लिहाज से यह मुईजू की पांच महीनों में दूसरी भारत यात्रा है.

जानकारों का कहना है कि मुईजू और मोदी की मुलाकात और उसके बाद की गई घोषणाएं दिखाती हैं कि दोनों देशों के रिश्ते नया मोड़ ले रहे हैं. भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के संस्थान मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस की एसोसिएट फेलो गुलबिन सुल्ताना कहती हैं कि भारत ने मालदीव की काफी मदद भी की है और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए क्षेत्र भी चिन्हित किए गए हैं.

उन्होंने बताया, "दोनों देश स्थानीय मुद्राओं में व्यापारिक लेन देन की शुरुआत करने पर सहमत हो गए और यह काफी महत्वपूर्ण होगा, विशेष रूप से ऐसे समय में जब मालदीव विदेशी मुद्रा के संकट से गुजर रहा है." गुलबिन ने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि भारत ने मालदीव की अर्थव्यवस्था के विविधीकरण के प्रयासों को भी समर्थन देने का फैसला किया है. इसके तहत भारत कृषि, मछली पालन, 'ओशियेनोग्राफी और ब्लू इकॉनमी' जैसे क्षेत्रों में शोध और विकास में मालदीव का सहयोग करेगा. गुलबिन इसे काफी महत्वपूर्ण घोषणा मानती हैं. मालदीव की अर्थव्यवस्था इस समय आर्थिक संकट से गुजर रही है. इस साल की पहली तिमाही में मालदीव का विदेशी ऋण 3.37 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जो उसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 45 प्रतिशत के बराबर है. देश के पास विदेशी मुद्रा का भंडार भी बहुत कम बचा है. इन हालात में मालदीव की मदद करने के लिए भारत ने मुद्राओं की अदला-बदली के एक समझौते की भी घोषणा की, जिसके तहत भारत मालदीव को 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर के अलावा 30 अरब रुपयों की मदद देगा. मुईजू ने इसके लिए भारत को शुक्रिया कहा.

वरिष्ठ पत्रकार संजय कपूर का मानना है कि यह समझौता मालदीव के लिए एक बड़ी मदद है. उन्होंने कहा, "स्पष्ट है कि दोनों देशों को यह अहसास हो गया है कि उन्हें एक दूसरे की जरूरत है." हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मुईजू जिस उद्देश्य से भारत आए थे वह पूरा हो पाया या नहीं. भारत आने से पहले उन्होंने बीबीसी को बताया था कि भारत को उसकी वित्तीय हालत की पूरी जानकारी है और "हमारे सबसे बड़े विकास साझेदारों में से एक होने के नाते भारत हमेशा हमारे बोझ को कम करने के लिए तैयार रहेगा."

दुर्बल रहना अपराध : मोहन भागवत

विजयादशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर के रेशम बाग मैदान में 'शस्त्र पूजन' किया. दशहरा के अवसर पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम पर सभी की नजरें रहती है. पद्म भूषण और पूर्व इसरो प्रमुख के. राधाकृष्णन भी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में विजयादशमी मनाने के लिए एकत्रित होकर संघ प्रार्थना की. इस कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पूर्व इसरो प्रमुख के. सिवन ने हिस्सा लिया. इस दौरान मोहन भागवत ने भारत सरकार से बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद करने को कहा है.

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर मोहन भागवत ने कहा, "बांग्लादेश में वहां के स्थानीय कारणों की वजह से हिंसक तख्तापलट हुआ. इस दौरान एक बार फिर से हिंदू समाज के लोगों पर अत्याचार किए गए. उन अत्याचारों के विरोध में वहां का हिंदू समाज इस बार संगठित होकर स्वयं के बचाव में घर के बाहर आया इसलिए थोड़ा बचाव हुआ. लेकिन यह अत्याचारी कट्टरपंथी स्वभाव जब तक वहां है तब तक वहां के हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यक समुदायों के सिर पर खतरे की तलवार लटकी रहेगी."

बांग्लादेश से होने वाले अवैध घुसपैठ को लेकर उन्होंने कहा, "बांग्लादेश से भारत में होनेवाली अवैध घुसपैठ और उसके कारण उत्पन्न जनसंख्या असंतुलन गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है. देश में आपसी सद्भाव और देश की सुरक्षा पर भी इस अवैध घुसपैठ के कारण सवाल खड़े होते है. उदारता, मानवता और सद्भावना के पक्षधर सभी के, विशेष कर भारत सरकार और विश्वभर के हिंदुओं के सहायता की बांग्लादेश में अल्पसंख्यक बने हिंदु समाज को आवश्यकता रहेगी." उन्होंने आगे कहा, "असंगठित रहना और दुर्बल रहना यह दुष्टों के द्वारा अत्याचारों को निमंत्रण देना है. यह पाठ भी विश्व भर के हिंदू समाज को ग्रहण करना चाहिए. यह बात यहां रुकती नहीं है. अब वहां भारत से बचने के लिए पाकिस्तान से मिलने की बात हो रही है. ऐसे विमर्श खड़े कर और स्थापित कर कौन से देश भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है. इसको लेकर भी सरकार को सोचना होगा." अपने संबोधन में मोहन भागवत ने कहा, "लंबी गुलामी के बाद भारत के पुनरुत्थान के पीछे स्वामी दयानंद का हाथ है. उन्होंने अपने धर्म और मूल को समझा और जन की जागृति का महान प्रयास किया." अपने संबोधन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, "देश में धर्म और संस्कृति का उत्थान होना चाहिए. युवाओं को धर्म सही अर्थ पता होना जरूरी है. भारत आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है. पूरी दुनिया में भारत की साख तेजी से बढ़ रही है. युवा शक्ति ही देश को आगे लेकर जाएगी. पूरी दुनिया में लोग भारत को पीछे करने की कोशिश में लगे हुए हैं. ऐसी ही कुछ शक्तियां भारत में भी हैं."

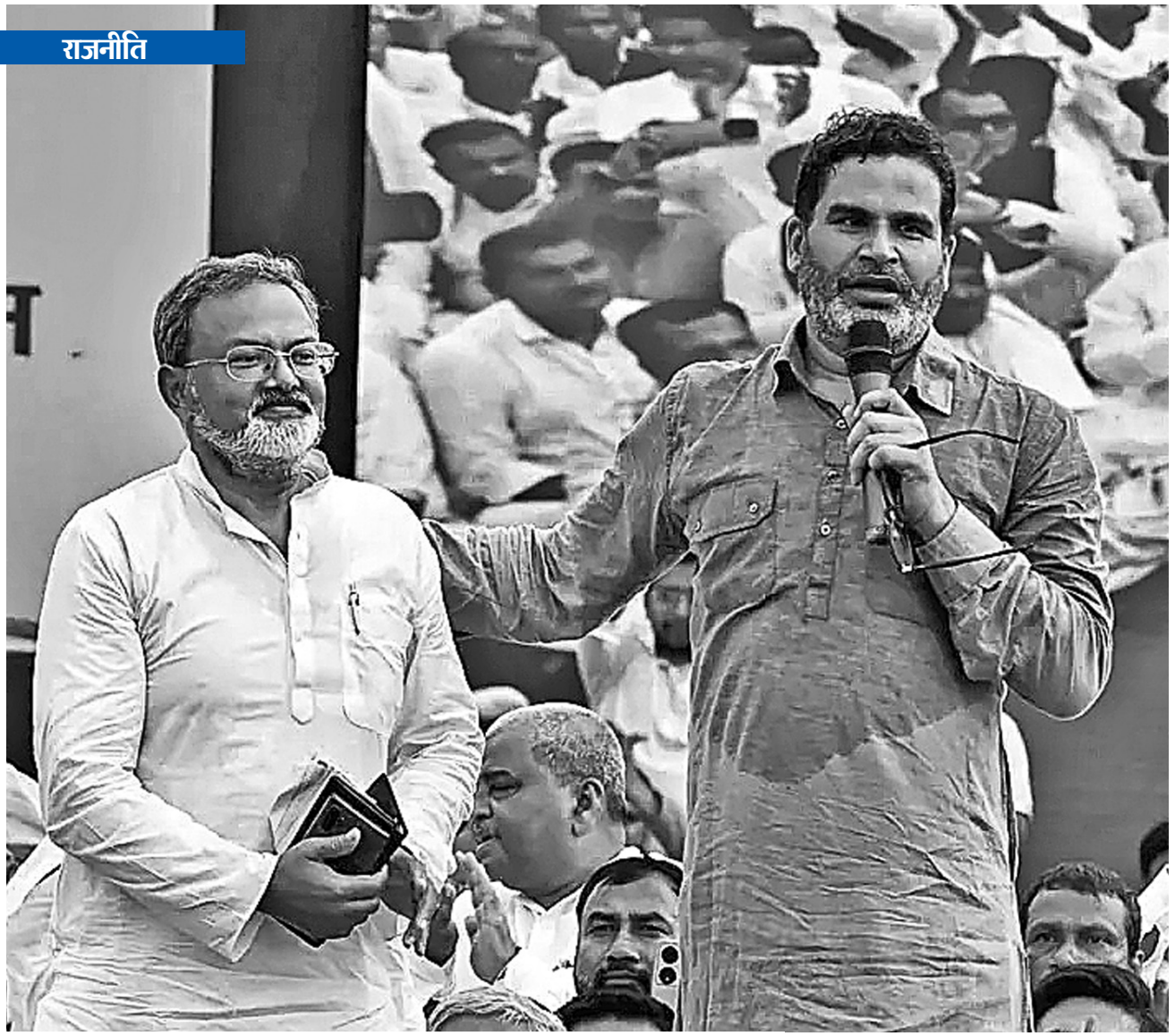

गांधी, आंबेडकर के सहारे क्या बिहार में बनेगी बात?

▪ सीटू तिवारी

चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जनसुराज लॉन्च कर दी है. बिहार की राजधानी पटना में दो अक्टूबर को अपनी पार्टी लॉन्च करते हुए प्रशांत किशोर ने पांच वादे किए. प्रशांत किशोर ने पार्टी का पहला कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती को बनाया है. ''जनसुराज पार्टी'' लॉन्च होने के बाद बिहार में राजनीतिक बयानबाज़ी भी तेज़ हो गई है.

पर सवाल ये है कि आख़िर प्रशांत किशोर की नई पार्टी के वादे क्या हैं? पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन हैं और इस पूरी सियासी घटना के मायने क्या हैं?

कौन हैं मनोज भारती?

बिहार के मधुबनी ज़िले में पैदा हुए मनोज भारती रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी हैं. वो अनुसूचित जाति से आते हैं. उनकी शुरुआती पढ़ाई जमुई के एक सरकारी स्कूल में और बाद में नेतरहाट से हुई है. उनकी उच्च शिक्षा आईआईटी कानपुर और दिल्ली से हुई. आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई करते हुए उनका चयन भारतीय विदेश सेवा में हुआ. वो चार देशों में भारत के राजदूत रहे हैं. लेकिन मनोज भारती राजनीतिक गलियारों में नया नाम हैं.

वरिष्ठ पत्रकार फैजान अहमद कहते हैं, "प्रशांत किशोर ने अपने कहे मुताबिक एक दलित चेहरे को अध्यक्ष बना दिया है लेकिन पार्टी चलाने के लिए नेता होना जरूरी है. जो मनोज भारती नहीं हैं. वो पढ़े लिखे हैं लेकिन पॉलिटिक्स में क्या कर पाएंगे, ये देखना होगा."

पार्टी लॉन्च करने के दौरान प्रशांत किशोर ने बताया कि जनसुराज ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ संविधान निर्माता बी आर आंबेडकर की तस्वीर वाले झंडे का आधिकारिक आवेदन चुनाव आयोग में दिया है. ऐसे में ये सवाल अहम है कि बीते दो साल से महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ जनसुराज अभियान चला रहे प्रशांत किशोर ने आंबेडकर को अपने झंडे में जगह क्यों दी?

बीजेपी के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष संजय पासवान इस कदम को 'वर्तमान समय की आवश्यकता' बताते हैं. वो कहते हैं, "पीके महात्मा गांधी और आंबेडकर को एक साथ लाकर नई पॉलिटिक्स की है. उनकी तैयारी बहुत लॉजिकल है. वो सत्तासीन पार्टियों के लिए ख़तरा साबित होंगे. अभी पार्टियां मध्यवर्ती जातियों पर फोकस कर रही हैं और इस बीच पीके ने एक दलित को अध्यक्ष बनाकर बहुत हिम्मत का काम किया है." प्रशांत किशोर की राजनीति को पहले ही पॉलिटिकल थिंकर्स 'डीईएम' यानी दलित, अति पिछड़ा और मुसलमान, केंद्रित बता रहे हैं.

बिहार में हुई जातिगत गणना में दलितों की आबादी 19.65 फीसदी, अति पिछड़े 36.01 फ़ीसदी और मुस्लिम 17.70 फ़ीसदी हैं.

पूर्व डीजी होमगार्ड और जनसुराज के संस्थापक सदस्यों में से एक राकेश कुमार मिश्र कहते हैं, "आज

की राजनीति में हमारी लड़ाई धर्म आधारित राजनीति करने वालों से है. मुख्यतौर पर बीजेपी से. धर्म आधारित राजनीति ने हमारे राजनीतिक पूर्वजों को अपने फायदे के लिए अलग कर दिया है, लेकिन हम दोनों को एक ही झंडे में लाकर गांधीवादियों और आंबेडकरवादियों को एक होने का संदेश देना चाहते है." लेकिन पार्टी बनने की पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा अहम प्रशांत किशोर ने पार्टी में खुद को ''बैकस्टेज या नेपथ्य'' में रखा है.

जनसुराज पार्टी लॉन्च होने से पहले बातचीत में उन्होंने कहा, ''पार्टी बनने के बाद जो काम मैं पिछले दो साल से कर रहा हूं, वही काम आगे करता रहूंगा. मैं अभी अररिया – सुपौल इलाके की यात्रा कर रहा था. दो- तीन दिन बाद उसी इलाके में वापस जाकर यात्रा करूंगा. जब तक लोगों को जागरुक नहीं करूंगा, मेरी यात्रा जारी रहेगी."

प्रशांत किशोर खुद को ''बैकस्टेज'' में क्यों रख रहे हैं?

इस सवाल पर जनसुराज के राकेश कुमार मिश्रा कहते हैं, "प्रशांत बैकस्टेज में नहीं कोर में हैं. हमारी पार्टी का काम करने का पैटर्न बिल्कुल अलग है. हमारे काम को दो स्तरों पर देखिए. पहला जनसुराज अभियान जिसका मुख्य काम बिहार की जनता को जागरुक करना है. दूसरा है संगठन जिसका दायित्व मनोज भारती जी को दिया गया है. जनसुराज अभियान का काम हमारी आत्मा, हमारी वैचारिक जमीन को लीड तो प्रशांत ही कर रहे हैं."

हालांकि, वरिष्ठ पत्रकार फैजान अहमद इसे जाति के संदर्भ से देखते हैं.

वो कहते हैं, "बिहार में चुनाव अभी एक साल दूर है. इसलिए अभी पीके को अपना चेहरा दिखाने की बहुत ज़रूरत नहीं है. यहां तीन दशकों की पॉलिटिक्स भी देखें तो उसमें अपर कास्ट का बहुत रोल नज़र नहीं आता है. प्रशांत किशोर ब्राह्मण हैं, इसलिए भी उन्होंने खुद को पीछे और एक दलित चेहरे को सामने रखा है."

''कांशीराम ने भी मायावती को आगे रखा था''

वरिष्ठ पत्रकार अरविंद शर्मा इसमें बहुजन पार्टी के संस्थापक कांशीराम का जिक्र लाते हैं. वो कहते हैं, "कांशीराम जी ने भी मायावती को आगे बढ़ाकर काम किया था और यूपी की राजनीति जो अपरकॉस्ट और ओबीसी के हाथ में थी, उसको दलितों के हाथ में लाए. हालांकि, बिहार में दलित आबादी में से पासवान जाति के नेता चिराग पासवान हैं, इसलिए पीके दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर काम कर रहे हैं." पत्रकार अरविंद शर्मा कहते हैं, "नीतीश कुमार के स्वास्थ्य, बीजेपी का चेहरा विहीन होना और राजद का लालू के साए से ना निकल पाने के चलते बिहार में एक पॉलिटिकल वैक्यूम है. ऐसे में पीके की पार्टी लॉन्च करने की टाइमिंग परफेक्ट है."

'कंट्रीब्यूशन ऑफ महादलित इन डेवलेपमेंट ऑफ बिहार इकोनॉमी' के लेखक और वरिष्ठ पत्रकार अरुण श्रीवास्तव प्रशांत किशोर के लिए 'कंफ्यूज्ड' शब्द का इस्तेमाल करते हैं. वो कहते है, " पीके का कद बहुत बढ़ा चढ़ाकर मीडिया प्रोजेक्ट कर रही है. जबकि अभी उन्हें पॉलिटिकल इकोनॉमी की भी ठीक समझ नहीं है."

जनसुराज पार्टी लॉन्च होने के बाद राजनीतिक बयानबाज़ी भी तेज हो गई है.

जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद कहते हैं, "पीके राजनीतिक रूप से किशोर हैं. ये दलितों को आगे करके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं. उनकी पार्टी लॉन्च हुई दो अक्टूबर को, जिस दिन पूरे देश में शराब की दुकानों को बंद रखा जाता है, लेकिन उसी दिन ये शराबबंदी खत्म करने की घोषणा कर रहे हैं."

वहीं राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन कहते हैं, "बीजेपी ने इनको राजद को डैमेज करने के लिए लॉन्च किया है, लेकिन ये बीजेपी के लिए ही आत्मघाती साबित होंगे."

प्रशांत किशोर की चुनावी सफलता भविष्य के गर्भ में है. लेकिन प्रशांत किशोर बीते दो सालों से बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर रहे हैं. देखना होगा कि वो अपने इस 'मोमेंटम' को कितना बरकरार रखते हुए उसे चुनावी सफलता में तब्दीलजनसुराज पार्टी लॉन्च होने के बाद राजनीतिक बयानबाज़ी भी तेज हो गई है.

प्रशांत किशोर की पार्टी के ''पांच वादे''

- सत्ता मिलने पर एक घंटे के अंदर शराबबंदी खत्म, उससे मिलने वाले राजस्व से विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था करना.
- हर युवा के हाथ में बिहार में ही रोजगार.
- 60 साल से ज्यादा उम्र वाले बुज़ुर्गों को प्रति माह 2,000 रुपये की पेंशन.
- महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए 4 प्रतिशत ब्याज पर पूंजी उपलब्ध कराना.
- बिहार के किसानों को पेट भरने वाली खेती से कमाऊ खेती की तरफ ले जाना. ये वादे करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, " पार्टी सत्ता में आई तो ये काम होंगे. जनसुराज देश का पहला ऐसा दल है जो राइट टू रिकॉल लागू करेगा. हमारे दल में जनता ही अपने उम्मीदवारों का चयन करेगी." मनोज भारती का नाम कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर घोषित करते हुए प्रशांत किशोर ने उनको 'खुद से भी ज्यादा काबिल' बताया.

पार्टी लॉन्च हुई दो अक्टूबर को, जिस दिन पूरे देश में शराब की दुकानों को बंद रखा जाता है, लेकिन उसी दिन ये शराबबंदी खत्म करने की घोषणा कर रहे हैं."

वहीं राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन कहते हैं, "बीजेपी ने इनको राजद को डैमेज करने के लिए लॉन्च किया है, लेकिन ये बीजेपी के लिए ही आत्मघाती साबित होंगे."

प्रशांत किशोर की चुनावी सफलता भविष्य के गर्भ में है. लेकिन प्रशांत किशोर बीते दो सालों से बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर रहे हैं. देखना होगा कि वो अपने इस 'मोमेंटम' को कितना बरकरार रखते हुए उसे चुनावी सफलता में तब्दील कर पाते हैं. कर पाते हैं.

नक्सलवाद के खिलाफ छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की रणनीति की हुई सराहना

देश के नक्सल प्रभावित राज्यों में जारी नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियानों पर एक अहम बैठक पिछले दिनों नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (और अन्य नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया।

इस महत्वपूर्ण बैठक का केंद्र बिंदु छत्तीसगढ़ का हाल ही में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ नक्सल विरोधी ऑपरेशन था, जिसमें राज्य की पुलिस ने 31 नक्सलियों को ढेर किया। इस ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ पुलिस की कुशल रणनीति और राज्य सरकार की योजनाओं की सफलता पर विशेष चर्चा की गई। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय तथा छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उनकी टीम के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जनवरी से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों ने लगभग 194 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराए हैं। वहीं 801 नक्सली गिरफ्तार हुए एवं 742 नक्सलियों ने आत्म समर्पण किया है। उन्होंने कहा आज भी जो युवा नक्सलवाद में लिप्त है उनसे आग्रह है कि हथियार छोड़ कर मुख्य धारा से जुड़े। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वास के लिए बेहतर योजनाएं बनाई हैं उसका फायदा लीजिए।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में नक्सल ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे राज्य पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने महीनों की मेहनत और प्लानिंग के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ऑपरेशन में करीब 1000 जवान शामिल थे, जिन्होंने 15 किलोमीटर के दायरे में स्थित गवाड़ी पहाड़ को घेरकर 31 नक्सलियों को ढेर किया। इस ऑपरेशन में कई बड़े नक्सली नेता मारे गए, जिनमें 16 पर कुल 1 करोड़ 30 लाख का इनाम घोषित था। मुठभेड़ में 18 पुरुष और 13 महिला नक्सली मारे गए।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि कैसे राज्य की पुलिस फोर्स ने सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।

मुख्यमंत्री ने बैठक में केवल ऑपरेशन की सफलता पर ही नहीं, बल्कि राज्य में चल रहे विकास कार्यों पर भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि "नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति बढ़ाई गई है। हम निरंतर गाँवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।" श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लगातार मिल रहे मार्गदर्शन में हमने माओवादियों के कोर को तोड़ा। ऐसे एरिया में हमने 32 नये कैम्प स्थापित किये हैं, जिसे वो अपनी राजधानी तक कहते थे। उनकी बटालियन के कमांडर हिड़मा के गाँव में भी हमने कैंप स्थापित किया और उसकी माँ को भी स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई।

भविष्य की योजनाओं और लक्ष्य की दी जानकारी : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ सरकार की आगे की योजनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य नक्सलियों के बचे हुए गढ़ों को समाप्त करना और इन इलाकों में स्थाई शांति और विकास सुनिश्चित करना है। निकट भविष्य में, दक्षिण बस्तर में 29 नए सुरक्षा कैंपों की स्थापना की जाएगी, ताकि नक्सलियों के प्रभाव को खत्म किया जा सके।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा केंद्र हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में हुए सफल ऑपरेशन की तारीफ करते हुए अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया कि वे भी छत्तीसगढ़ की खुफिया तकनीकी और आपसी समन्वय के आधार पर अपने अपने राज्यों में ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सहित अन्य नक्सल प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए पूरा समर्थन देगी।

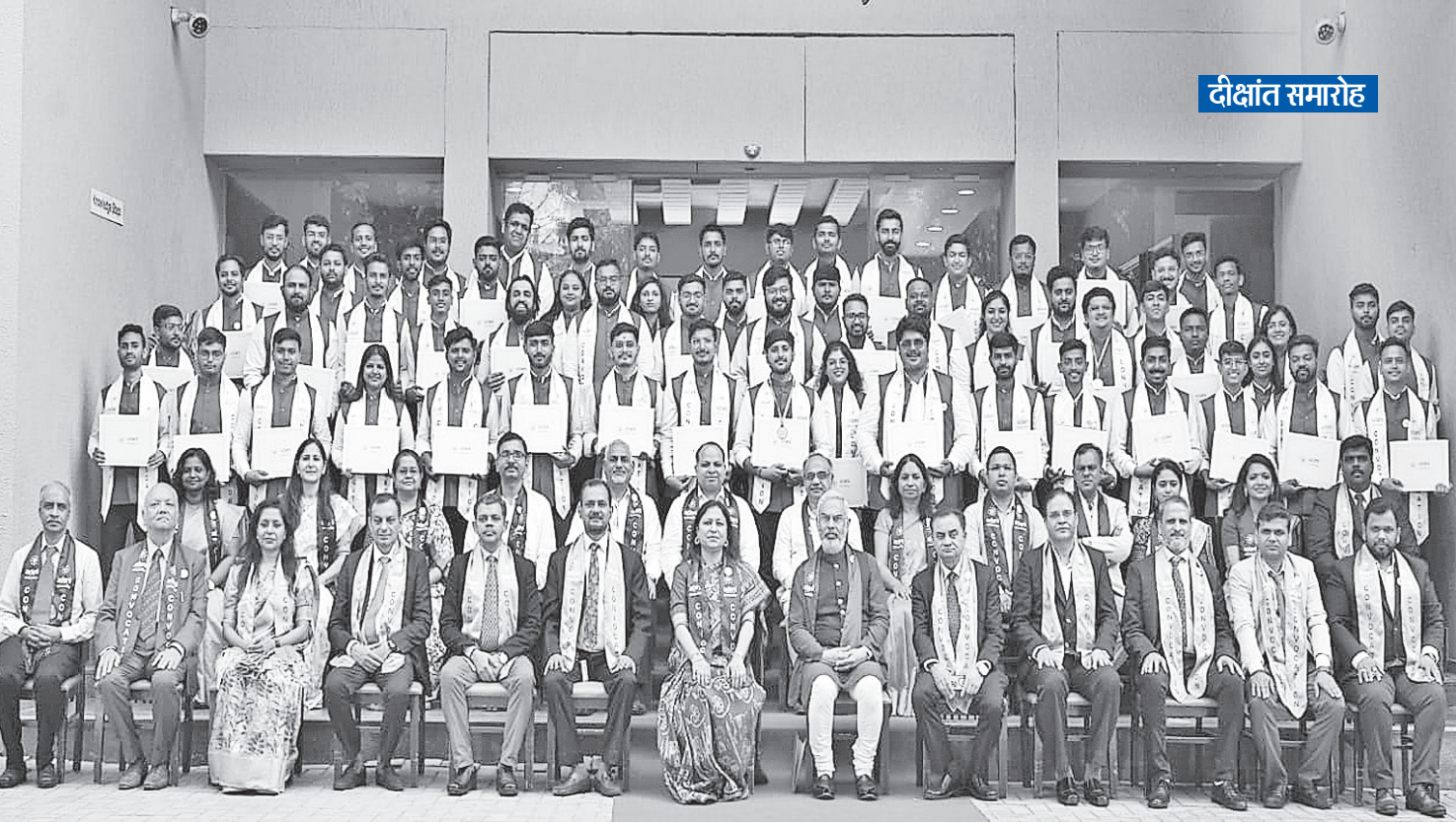

अदाणी विश्वविद्यालय ने मनाया अपना पहला दीक्षांत समारोह

अदाणी विश्वविद्यालय ने अपने शांतिग्राम परिसर में अपना पहला दीक्षांत समारोह मनाया, जो संस्थान की शैक्षणिक उत्कृष्टता की यात्रा में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन को दर्शाता है। पद्म श्री कार्तिकेय विक्रम साराभाई, जो दुनिया के प्रमुख पर्यावरण शिक्षा के विशेषज्ञों में से एक हैं और सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन (सीईई) के संस्थापक और निदेशक हैं, ने दीक्षांत संबोधन दिया। इस समारोह की अध्यक्षता अदाणी विश्वविद्यालय की अध्यक्ष डॉ. प्रीति अदाणी ने की।

69 पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों ने एमबीए (इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट), एमबीए (एनर्जी मैनेजमेंट) और एमटेक (कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट) प्रोग्राम्स में अपनी डिग्रियां प्राप्त कीं, जबकि 4 छात्रों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक दिए गए। यह दीक्षांत समारोह उनके लिए अदाणी विश्वविद्यालय के गौरवान्वित एंबेसडर के रूप में अपनी यात्रा की शुरुआत को रेखांकित करता है।

ग्रेजुएट्स को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री कार्तिकेय साराभाई ने कहा, "जब आप इस नए अध्याय की शुरुआत करते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप उन चुनौतियों पर विचार करें जिनका आप सामना करेंगे, और उन स्किल्स को पहचानें जिन्हे आपको प्रभावी रूप से नेविगेट करने की आवश्यकता होगी।"

श्री साराभाई ने विकास में समावेशिता की

69 पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों ने एमबीए (इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट), एमबीए (एनर्जी मैनेजमेंट) और एमटेक (कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट) प्रोग्राम्स में अपनी डिग्रियां प्राप्त कीं, जबकि 4 छात्रों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक दिए गए।

आवश्यकता पर जोर दिया और फ्यूचर लीडर्स से समुदायों के साथ जुड़ने तथा विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के साथ सहयोग करने की अपील की। उन्होंने तकनीकी परिवर्तन के प्रभाव पर भी बात की, यह कहते हुए कि टेक्नोलॉजी को सशक्त बनाना चाहिए, न कि उसका बहिष्कार करना चाहिए।

अपने संबोधन में, डॉ. प्रीति अदाणी ने अदाणी विश्वविद्यालय की स्थापना में सीनियर लीडरशिप, फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लगातार प्रयासों को सराहा, जिसे 2022 में औपचारिक मंजूरी मिली। शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करते हुए, डॉ. अदाणी ने कहा, "शिक्षा में कभी न गिनी जा सकने वाली चमक है।" उन्होंने "आत्मनिर्भर भारत" के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, लाइफ साइंस में रिसर्च और इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया।

उन्होंने कहा, "विफलताएँ आपको बड़ी प्रगति के रास्ते पर ले जाने में मदद करती हैं," और उनसे सेटबैक्स को विकास के अवसरों के रूप में देखने की सलाह दी।

उन्होंने अदाणी विश्वविद्यालय को वैश्विक पहचान प्राप्त करने की अपनी आकांक्षा व्यक्त की, और ग्रेजुएट्स से अपील की कि वे अपने अल्मा मेटर के एंबेसडर बनें और अपने ज्ञान का समाज के उत्थान के लिए उपयोग करें।

उन्होंने ग्रेजुएट्स को व्यावसायिक दुनिया के परिवर्तनों और चुनौतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया, यह कहते हुए कि ज्ञान, स्थिरता, तर्कशीलता, और बुद्धिमत्ता में निहित उत्कृष्टता उन्हें अलग करेगी।

अदाणी विश्वविद्यालय के प्रॉवोस्ट, प्रोफेसर रवि पी सिंह, ने अदाणी विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से प्राप्त अकादमिक माइलस्टोन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2023-24 के वर्ष के लिए विश्वविद्यालय की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए, प्रोफेसर सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष में, हमने अदाणी विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण माइलस्टोन प्राप्त किए हैं।

प्रोफेसर सिंह ने कहा "अदाणी समूह के प्रोफेशनल्स के साथ हमारी साझेदारी कक्षाओं में वास्तविक दुनिया की अंतर्दृष्टि को शामिल कर के, लर्निंग एक्सपीरियंस को और अधिक समृद्ध बनाती है। छात्रों ने प्रमुख साइट्स की विजिट और कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हाथों-हाथ अनुभव प्राप्त किया।"

इस दीक्षांत समारोह में गवर्निंग बॉडी, बोर्ड ऑफ़ मैनेजमेंट, अकादमिक कॉउन्सिल, बोर्ड ऑफ़ स्टडीज और कॉर्पोरेट व अकादमिक तथा अनुसंधान समुदाय के कई प्रतिष्ठित अतिथियों के साथ-साथ ग्रेजुएट होने वाले छात्रों और उनके माता-पिता ने भाग लिया।

सुरदा माइंस में फिर से खनन शुरू, 100 करोड़ की राजस्व की होगी प्राप्तिः सतीश चंद्र दुबे

घाटशिला अनुमंडल स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मुसाबनी सुरदा माइंस का उद्घाटन किया गया. केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे और झारखंड सरकार के मंत्री रामदास सोरेन ने इसका उद्घाटन किया. इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे.

केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने सभा स्थल पहुंचने पर सबसे पहले कंपनी के पदाधिकारी के साथ पौधा रोपण किया. इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए कहा कि तांबे के मामले में देश की आत्मनिर्भरता की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे विभिन्न करों के रूप में 100 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी. सुरदा खान से उत्पादन प्रारम्भ होने से भारी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा. भविष्य में सुरदा खान की क्षमता को 0.4 मिलियन टन से बढ़ा कर 0.9 मिलियन टन प्रति वर्ष किया जाएगा.

झारखण्ड सरकार ने दिनांक 6 जनवरी, 2022 को 20 वर्षों के लिए सुरदा खदान के लीज की अनुमति प्रदान की थी. कुछ तकनीकी एवं वैधानिक खामियों के कारण सुरदा खदान से उत्पादन प्रारम्भ नहीं हो सका. अंततः कंपनी पदाधिकारियों द्वारा उन सभी तकनीकी और वैधानिक खामियों को दूर किया गया. 29 अगस्त, 2024 को झारखंड कैबिनेट की बैठक में माइनिंग लीज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया.

तत्पश्चात झारखंड के खनन एवं भूगर्भ विभाग द्वारा 06 सितंबर, 2024 को 20 वर्षों के लीज विस्तार के लिए पत्र जारी किया गया और दिनांक 26 सितंबर, 2024 को लीज डीड निष्पादित हो गया एवं 28 सितंबर को लीज रजिस्टर हो गई. इसके साथ ही झारखंड कैबिनेट ने दिनांक 20.09.2024 को हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के राखा एवं केन्दाडीह खदानों के लीज विस्तारीकरण का प्रस्ताव भी पारित कर दिया है.

जल्द ही कंपनी इन खदानों को प्रारंभ करने की दिशा में आगे बढ़ेगी और एक साल की अवधि के भीतर इन खदानों से उत्पादन प्रारम्भ हो जाएगा. जिससे आई.सी.सी. की अयस्क उत्पादन क्षमता में तीन गुणा बढ़ोत्तरी होगी. राखा और केन्दाडीह खदानों के चालू होने से लगभग 2000 स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार की प्राप्ति होगी. अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10,000 स्थानीय लोग इससे लाभान्वित होंगे.

> सुरदा खदान से उत्पादन शुरू होने से लगभग 1100 स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष और 5000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा तथा जन कल्याण और सीएसआर गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा खनन कार्यों के लिए वर्ष 2024-25 के दौरान 50 करोड़ का पूंजीगत निवेश किया जाएगा.
>
> **– घनश्याम शर्मा,** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

स्वच्छता अभियान में सम्मिलित हुआ नवरत्न' लोक उद्यम नालको

स्वच्छता ही सेवा 2024 के राष्ट्रव्यापी अभियान में खान मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के 'नवरत्न' लोक उद्यम, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) भी शामिल हुआ। खान मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, स्वैच्छिक 'श्रम दान' गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और स्वच्छता के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2024 के दौरान 'स्वच्छता ही सेवा' पखवाड़ा मनाया गया।

नालको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री श्रीधर पात्र के नेतृत्व में कंपनी की सभी परिचालन इकाइयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों, सीआईएसएफ तथा संविदा कर्मियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। इस पहल के अंतर्गत, नालको ने बहु-स्थानीय सामूहिक स्वच्छता अभियान, सामूहिक वृक्षारोपण अभियान, स्वास्थ्य शिविर सह स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए और पीपीई किट, सुरक्षा किट, स्वच्छता किट आदि का वितरण किया। इसके अलावा, पखवाड़ा अभियान के दौरान प्रश्नोत्तरी, कविता पाठ, चित्रकला प्रतियोगिता सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों, छात्रों और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया।

अभियान के दौरान नालको ने अनुगुळ और दामनजोड़ी में अपनी परिचालन इकाइयों में कई स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों को भी अपनाया, जो पर्यावरणीय स्थिरता और सामुदायिक जुड़ाव के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता हैं। स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाने के लिए अनुशासन की भावना पैदा करने के अलावा अभियान से प्रतिभागियों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रति वर्ष 100 घंटे समर्पित करने और दूसरों के बीच स्वच्छता प्रथाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भी प्रोत्साहन मिला। अभियान का समापन 2 अक्टूबर, 2024 को 'राष्ट्रपिता' महात्मा गांधी की जयंती पर कंपनी के कार्यस्थलों, कार्यालयों और आवासीय प्रतिष्ठानों को साफ और स्वच्छ रखने में 'सफाई मित्रों'- सफाई कर्मचारियों के योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें सम्मानित करने के साथ हुआ।

नाबार्ड ने झारखंड को दी 770 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी

झारखंड में सिंचाई की दो परियोजनाओं के निर्माण के लिए 770 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने यह जानकारी दी। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

झारखंड में नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक एस.के. जहागीरदार ने बताया, ''नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत पलामू और गिरिडीह जिले में सिंचाई की दो परियोजनाओं के निर्माण के लिए 769.58 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है।''

उन्होंने बताया कि सिंचाई परियोजना के एक बार पूरा हो जाने के बाद पलामू के आठ प्रखंडों में पाइपलाइन के माध्यम से अतिरिक्त 11,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। नाबार्ड के अनुसार, दोनों परियोजनाओं से इन जिलों में कृषि से जुड़े कार्यों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।

बैंक की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया, "इस वित्तीय सहायता को मंजूरी देने के साथ ही वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आरआईडीएफ के तहत झारखंड को 1,017 करोड़ रुपये की मदद दी जा चुकी है। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की स्थापना के बाद से झारखंड को प्रदान की गई सहायता अब लगभग 24,300 करोड़ रुपये हो गई है।"

शिव शक्ति, रीइंजीनियरिंग इमोशन्स और आईलाइट ग्लोबल द्वारा एक विशेष दीवाली शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें गरीब बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास किया गया। डॉ. राजीव नागपाल और शैलेश के समर्थन से यह शिविर बेहद सफल रहा। इसमें मनोवैज्ञानिक अदिति भसीन की उपस्थिति भी खास रही। बच्चों ने दीवाली के दृश्य चित्रित किए, पटाखे जलाए और पेपर क्राफ्ट बनाए। उनके चेहरे पर आई मुस्कान इस बात का प्रतीक थी कि छोटी-छोटी खुशियाँ भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं।

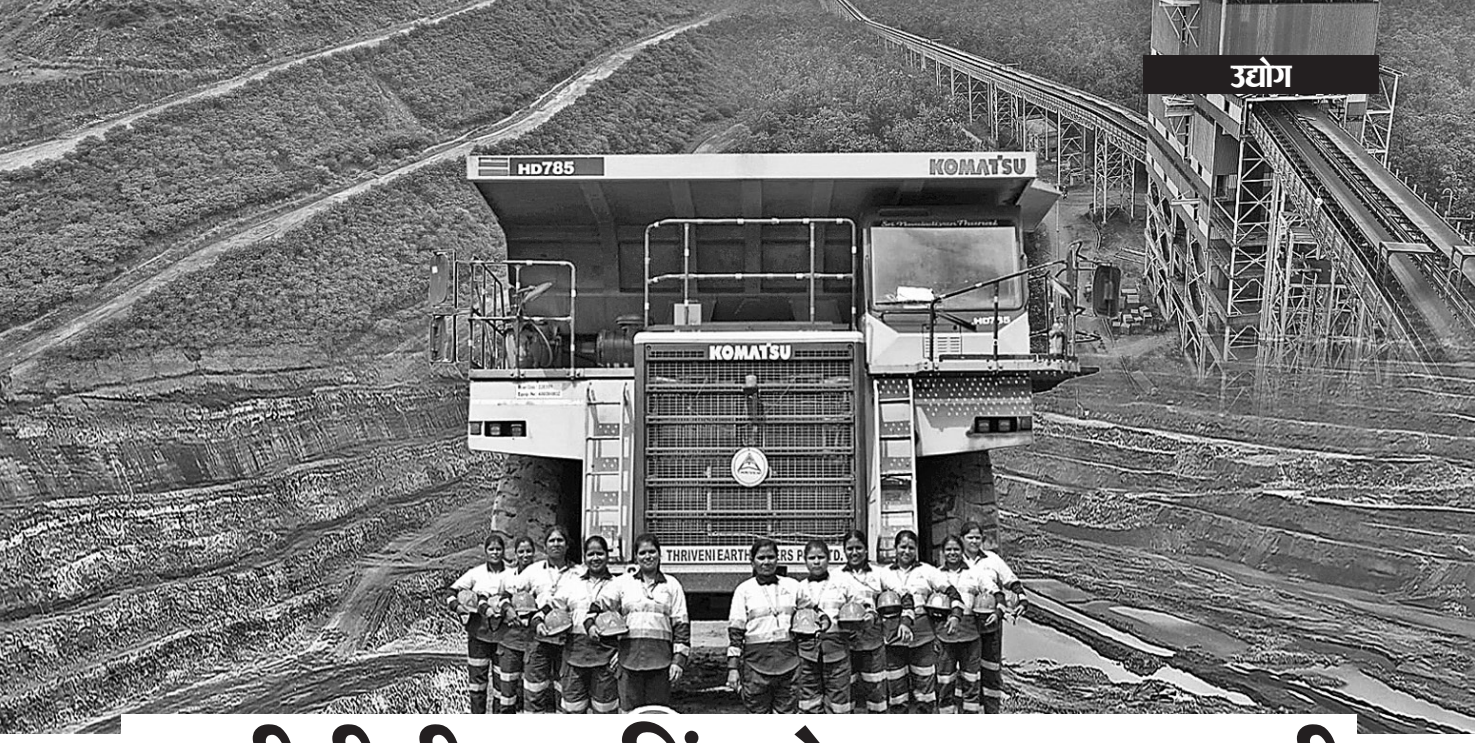

एनटीपीसी माइनिंग ने 2024-25 की पहली छमाही में शानदार प्रदर्शन किया

एनटीपीसी माइनिंग ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में 19 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) से अधिक कोयले का उत्पादन करके शानदार प्रदर्शन किया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि दर्ज करता है और एनटीपीसी के बिजली स्टेशनों को लगभग 16% की वृद्धि के साथ 19.7 एमएमटी कोयला भेजा है।

झारखंड के हजारीबाग क्षेत्र में बहुत भारी वर्षा के बावजूद, जहाँ एनटीपीसी की अधिकांश कोयला खदानें स्थित हैं, कंपनी ने वित्त वर्ष 24-25 की दूसरी तिमाही में 9.30 एमएमटी उत्पादन दर्ज किया है, जबकि वित्त वर्ष 23-24 की दूसरी तिमाही में 7.45 एमएमटी उत्पादन हुआ था। इस तरह उत्पादन में 25% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। डिस्पैच के मोर्चे पर, एनटीपीसी खनन ने दूसरी तिमाही में 14.5% की वार्षिक वृद्धि हासिल की है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न बिजली घरों को लगभग 9.5 एमएमटी कोयला डिस्पैच किया गया है।

एनटीपीसी कोल माइनिंग ने लगातार अपने उत्पादन लक्ष्यों को पार किया है, जिससे कैप्टिव कोल माइनिंग क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत हुई है। भविष्य को देखते हुए, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक उत्पादन लक्ष्य को पिछले वर्ष के 34 एमएमटी उत्पादन लक्ष्य की तुलना में उत्तरोत्तर बढ़ाकर 40 एमएमटी कर दिया गया है और खनन टीम अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

आज तक, एनटीपीसी माइनिंग ने 123 एमएमटी से अधिक कोयला उत्पादन किया है और अपनी पांच चालू कैप्टिव कोयला खदानों से 121 एमएमटी से अधिक कोयला भेजा है, जिनमें झारखंड में स्थित पकरी बरवाडीह, केरेन्डारी और चट्टी बरियातू, ओडिशा में दुलंगा और छत्तीसगढ़ में तलाईपल्ली शामिल हैं। इससे एनटीपीसी के ताप विद्युत स्टेशनों के लिए ईंधन सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, जो देश के हर चौथे बल्ब को रोशन कर रहा है।

एनटीपीसी माइनिंग का मजबूत प्रदर्शन ' विकसित भारत' के दृष्टिकोण के साथ संरेखित ऊर्जा ' आत्मनिर्भरता ' के प्रति इसके संकल्प को दर्शाता है।

कोयले का उत्पादन अगस्त तक 384 मिलियन टन तक पहुंचा

देश में समग्र कोयला उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। यह वित्त वर्ष 2024-25 में अगस्त, 2024 तक 384.08 मिलियन टन (अंतिम) तक पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में इसी अवधि के दौरान यह 360.71 मिलियन टन था, जो 6.48 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। अप्रैल से अगस्त, 2024 की अवधि के दौरान कोल इंडिया का उत्पादन बढ़कर 290.39 मिलियन टन हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 281.46 मिलियन टन हो गया। इसमें 3.17 प्रतिशत की वृद्धि है।

कैप्टिव और अन्य कंपनियों से भी कोयले के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। यह अप्रैल से अगस्त 2024 तक 68.99 मिलियन टन तक पहुंच गया। यह पिछले वर्ष की समान अवधि में 52.84 मिलियन टन की तुलना में 30.56 प्रतिशत की वृद्धि है। अगस्त, 2024 तक संचयी कोयला प्रेषण में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। अगस्त, 2024 तक संचयी कोयला प्रेषण वित्त वर्ष 2024-25 में 412.07 मिलियन टन (अनंतिम) था। यह वित्त वर्ष 2023-24 में इसी अवधि के दौरान 391.93 मिलियन टन था। यह 5.14 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

कोल इंडिया ने अप्रैल से अगस्त, 2024 तक 309.98 मिलियन टन कोयला भेजा। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान भेजे गए 305.37 मिलियन टन की तुलना में 1.51 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, कैप्टिव और अन्य कंपनियों ने 76.95 मिलियन टन का कोयला प्रेषण दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान भेजे गए 58.53 मिलियन टन की तुलना में 31.48 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि कोयला क्षेत्र की बेहतर रसद क्षमताओं और कोयले की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को उजागर करती है।

रांची, हटिया, कांके, मांडर व तमाड़ में 13 और सिल्ली-खिजरी में 20 नवंबर को मतदान

▪ 25,77,470 मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग, 92868 यूथ वोटर पहली बार डालेंगे वोट 13300 मैनपावर और 1000 से अधिक वाहन लगेंगे

झारखंड विधानसभा का चुनाव दो चरणों में होगा। रांची जिला के सात विधानसभा में भी दो चरणों में मतदान होगा। रांची, हटिया, कांके, मांडर और तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में 13 नवंबर और सिल्ली व खिजरी विधानसभा में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। पहले चरण के लिए 18 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। 25 अक्टूबर तक नामांकन होगा। 28 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी और 30 अक्टूबर को तक नाम वापस लिए जा सकते हैं।

दूसरे चरण के लिए 22 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। 29 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल होगा। 30 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी। 1 नवंबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे और 20 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को पंडरा बाजार समिति में मतगणना होगी। डीसी वरुण रंजन ने मंगलवार को पत्रकारों को बताया कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

जिले के सात विधानसभा में कुल 25 लाख 77 हजार 470 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 92,868 मतदाता 18 से 19 आयु वर्ग के हैं, जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल 32,521 दिव्यांग मतदाता हैं, उनके मतदान के लिए प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था की जाएगी। सभी मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर उपलब्ध रहेगा। उन्होंने बताया कि बेल पर बाहर कुख्यात अपराधियों को जिला बदर किया जाएगा। वारंटियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

रांची जिले में 23 नवंबर तक निषेधाज्ञा लागू : विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही रांची जिले में 23 नवंबर तक निषेधाज्ञा लगा दी गई है। सदर और बुंडू एसडीओ ने निर्देश जारी कर दिया है। धरना-प्रदर्शन, जुलूस-रैली पर रोक रहेगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

25,77,470 मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग, 92868 यूथ वोटर पहली बार डालेंगे वोट 13300 मैनपावर और 1000 से अधिक वाहन लगेंगे.

रांची जिले में 2777 मतदान केंद्र हैं। इसमें 2 मतदान केंद्र वाले 430 भवन हैं। 3 केंद्र वाले 120 भवन, 4 केंद्र वाले 69 और 5 से अधिक केंद्र वाले 65 भवन हैं। दोनों चरणों का चुनाव कराने के लिए 13300 कर्मचारियों को लगाया जाएगा। 333 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। चुनाव कराने के लिए लगभग एक हजार वाहनों की जरूरत पड़ेगी। इसकी भी सूची तैयार कर ली गई है। 15 कोषांग बनाए गए हैं। मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण भी चल रहा है।

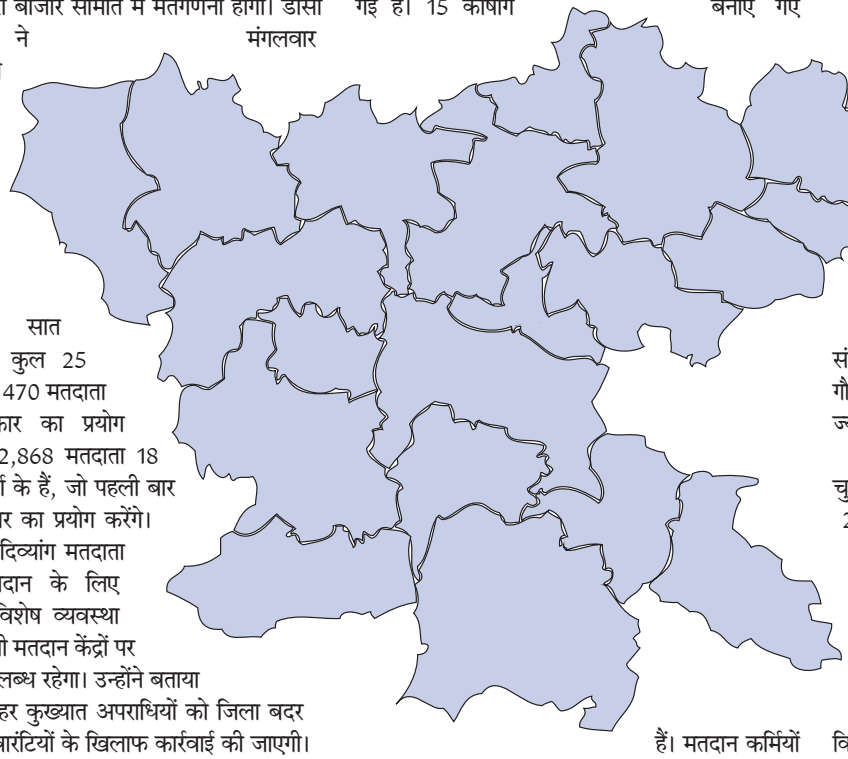

डीसी ने बताया कि जिले में 3500 हथियार का लाइसेंस जारी किया गया है। सभी हथियारों का सत्यापन कराकर जमा कराया जाएगा। सुविधा एप पर आवेदन करने के बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सभा, जुलूस और वाहन की अनुमति मिलेगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर अनुमति दी जाएगी। हेलीकॉप्टर की अनुमति डीसी देंगे। जिले में 5 हेलीपैड बनाए गए हैं। इसके अलावा 55 हेलीपैड आपात लैंडिंग के लिए चिह्नित किए गए हैं।

झारखंड विधानसभा चुनाव दो चरण में

झारखंड विधानसभा चुनाव दो चरण में होंगे। 13 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी, जिसमें 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे फेज की वोटिंग 20 नवंबर को होगी, जिसमें 38 सीट पर वोट डाले जाएंगे। 23 नवंबर को मतगणना होगी और नतीजे आएंगे।

राज्य गठन के बाद झारखंड में पहली बार दो चरण में विधानसभा का चुनाव गठन हो रहा है। राज्य के बाद अब तक चार बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। इनमें तीन बार पांच चरण में और एक बार तीन चरण में वोट डाले गए थे। इस बार दो चरण में ही 81 विधानसभा सीटों पर मतदान होने से क्या अतिरिक्त प्रभाव पड़ेंगे, वो मतदान के बाद ही सामने आएगा। लेकिन, यदि लोकसभा की तुलना में विधानसभा चुनाव में और अधिक मतदान हुए, तो हो संभव है कि स्पष्ट जनादेश मिल जाए अन्यथा आंकड़ों पर गौर करें तो कम वोट पड़ने पर त्रिशंकु विधानसभा बनने का ज्यादा चांस रहता है।

राज्य गठन के बाद वर्ष 2005 में पहला विधानसभा चुनाव तीन चरण में हुआ था। उसके बाद से वर्ष 2009, 2014 और 2019 में हुए विधानसभा चुनाव 5 चरणों में हुए थे। 2014 और 2019 में पांच चरणों में चुनाव के बाद भाजपा और झामुमो गठबंधन की बहुमत की सरकार बनी थी। वर्ष 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा बनी थी। जिसके बाद पहली बार झामुमो और भाजपा ने मिलकर सरकार बनाई थी।

राज्य बनने के बाद वर्ष 2004 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ था। इसमें 57.03% मतदान हुआ था, जो उसे कुछ माह पहले हुए लोकसभा चुनाव से 1.34 % अधिक था। मोटे तौर पर लोकसभा चुनाव की तुलना में विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत अधिक होता रहा है।

केवल 2014 और 2019 के चुनाव में मतदान प्रतिशत 63 से अधिक था। इन दोनों चुनावों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी।2004 के लोकसभा चुनाव में 55.69% मतदान हुआ था। 2019 के लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक 66.80 प्रतिशत वोट पड़े थे। दो चरण में कराए जा रहे चुनाव का एक कारण यह भी हो सकता है कि राज्य में नक्सली घटनाएं कम होने से सुरक्षा अब बड़ा सवाल नहीं रह गया है।

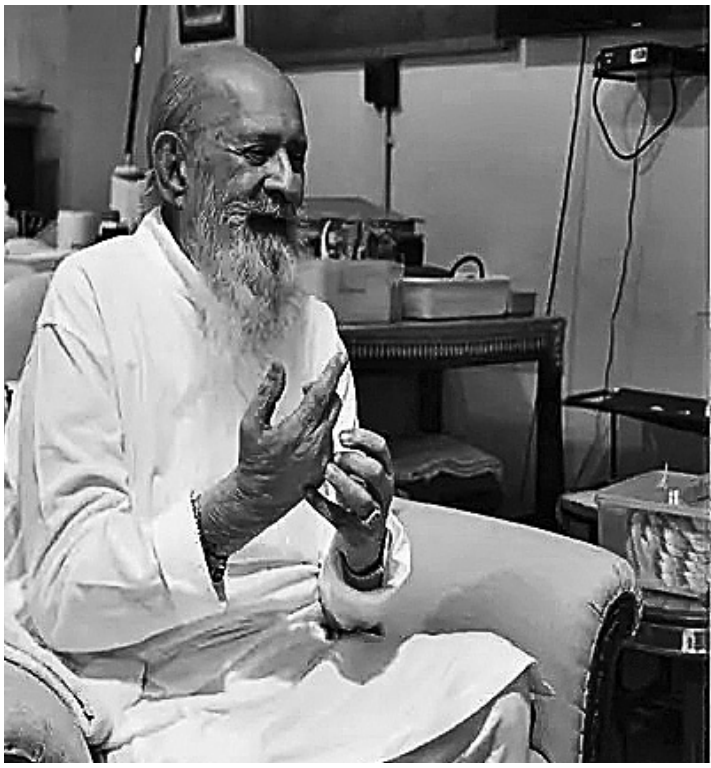

अजय जडेजा जामनगर राजघराने के वारिस घोषित; जामसाहब ने बनाया उत्तराधिकारी

भारतीय क्रिकेट टीम इस समय बांग्लादेश के खिलाफ टी -20 सीरीज खेल रही है। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भी टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इन सबके बीच एक स्टार भारतीय क्रिकेटर को बड़ी खुशखबरी मिली है। दरअसल पूर्व भारतीय दिग्गज क्रिकेटर अजय जडेजा की जामनगर के राजसी परिवार में एंट्री हुई है। जामनगर के महाराजा ने उन्हें अपना वारिस घोषित किया है।

जडेजा बने जामनगर रियासत के उत्तराधिकारी : अजय जडेजा को गुजरात की जामनगर रियासत का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। जामनगर के शाही परिवार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जाम साहब के वारिस के तौर पर जडेजा के नाम का ऐलान किया है। जाम साहब शत्रुशल्यसिंहजी महाराज ने खुद इस ऐतिहासिक फैसले की घोषणा की है।

जामनगर के महाराजा शत्रुशल्यसिंहजी की ओर से एक पत्र जारी कर अजय जडेजा को जामनगर राजघराने का अगला वारिस घोषित किया गया है।

बता दें कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा जामनगर के ही रहने वाले हैं। वो नवानगर रियासत से संबंध रखते हैं। जडेजा पहले से ही जाम साहब शत्रुशल्यसिंहजी के करीबी रहे हैं और माना जाता था कि वही अगले जाम साहब होंगे।

एक नजर जडेजा के क्रिकेट करियर पर : 53 साल के अजय जडेजा भारतीय क्रिकेट टीम के शानदार खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। उनके क्रिकेट करियर पर नजर डालें तो वो साल 1992 से 2000 तक टीम इंडिया का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने इस दौरान भारत के लिए कुल 211 इंटरनेशनल मैच खेले और कुछ में टीम के उप कप्तान भी रहे। जडेजा ने 196 वनडे मैचों में 5359, जबकि 15 टेस्ट मैचों में 576 रन बनाए। एक प्रख्यात भारतीय क्रिकेटर होने के अलावा जडेजा शाही जामनगर परिवार के वंशज हैं। मैच फिक्सिंग में नाम आने के बाद जडेजा के क्रिकेट खेलने पर बैन लग गया था। 2003 में हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने उन पर बैन हटा दिया था, लेकिन जडेजा इसके बाद क्रिकेट नहीं खेल पाए। वो आईपीएल में कई टीमों के मेंटॉर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अफगानिस्तान को भी कोचिंग दी थी।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप में मेंटॉर की भूमिका के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से फीस लेने से इनकार कर दिया था।

कैसा रहा जामनगर के वारिस का इतिहास? : जानकारी के मुताबिक मौजूदा जाम साहब शत्रुशल्यसिंहजी निसंतान हैं। इस वजह से उन्होंने पूर्व क्रिकेटर जडेजा को अपना वारिस चुना है। जाम साहब शत्रुशल्यसिंहजी के पिता दिग्विजय सिंह थे, जिन्होंने 33 साल तक जामनगर रियासत संभाली। उनके चाचा रणजीत सिंह जी ने गोद लिया था और अपना वारिस बनाया था। बता दें कि मशहूर भारतीय घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी जाम साहब रणजीत सिंह के नाम पर ही खेली जाती है। अजय जडेजा भी रणजीत सिंह जी और दिलीप सिंह जी के परिवार से ही आते हैं। यही वजह है कि शत्रुशल्यसिंहजी ने आधिकारिक तौर पर जडेजा को अपना वारिस घोषित किया है।

पत्र में शत्रुशल्यसिंहजी ने कहा

मुझे खुशी है कि अजय जडेजा नवानगर के नए जाम साहब होंगे। मुझे लगता है कि ये जामनगर की जनता के लिए आशीर्वाद रूप होगा।

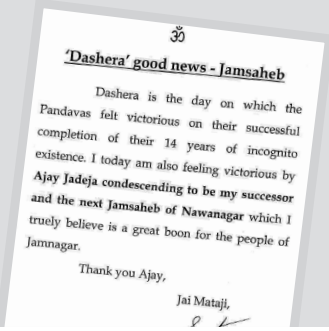

ॐ

'Dashera' good news - Jamsaheb

Dashera is the day on which the Pandavas felt victorious on their successful completion of their 14 years of incognito existence. I today am also feeling victorious by **Ajay Jadeja condescending to be my successor and the next Jamsaheb of Nawanagar** which I truely believe is a great boon for the people of Jamnagar.

Thank you Ajay,

Jai Mataji,

अर्जुन कपूर से ब्रेकअप का मलाइका को पछतावा नहीं

मलाइका अरोड़ा के पिता की हाल ही में मौत हो गई है। अपने पिता की मौत के सदमे से मलाइका अभी उभर ही रही हैं। पिता की मौत के दौरान उनके एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर से लेकर उनके एक्स हसबैंड अरबाज खान का परिवार उनके साथ खड़ा रहा। खान परिवार के सभी लोग मलाइका के साथ खड़े रहे थे। पिता की मौत के बाद मलाइका अरोड़ा ने ग्लोबल स्पा मैगजीन से बात की है। इस दौरान एक्ट्रेस ने अपनी लाइफ को फैसलों के बारे में बात की है। मलाइका का कुछ जवाब को फैंस उनके एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर से जोड़ रहे हैं।

जनवरी में आई जूम की रिपोर्ट के मुताबिक, मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर ने नवंबर 2023 में ही ब्रेकअप कर लिया था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दोनों में से कोई एक शादी कर सेटल होना चाहता था, जबकि दूसरा इसके लिए समय चाहता था। यही वजह उनकी अनबन का कारण बनी थी। ब्रेकअप की खबरें तब सुर्खियों में आईं जब मलाइका अरोड़ा ने अर्जुन और उनके रिलेटिव्स को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया। बताते चलें कि दोनों 2016 से रिलेशनशिप में हैं। कपल ने बर्थडे पोस्ट के जरिए अपने रिश्ते पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी।

तमन्ना भाटिया से ईडी ने की पूछताछ

तमन्ना भाटिया की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही है। आईपीएल 2023 से जुड़े एक मामले में इडी (प्रवर्तन निदेशाल) ने तमन्ना से गुवाहाटी में पूछताछ की। ईडी के सामने पेशी में उनसे महादेव बैटिंग ऐप और ऑनलाइन गेमिंग को लेकर सवाल पूछे गए। चंद महीने पहले भी उन्हें इसी मामले में महाराष्ट्र साइबर सेल ने तलब किया था। इस केस में फंसने वाली तमन्ना इकलौती सेलिब्रिटी नहीं हैं। इसमें अब तक कई सिंगर्स, एक्टर और कॉमेडियन इडी के रडार पर आ चुके हैं।

सलमान खान को फिर से धमकी

सलमान खान की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली। इसके बाद उनका सीधा निशाना सलमान खान हैं, इस बात की पुष्टि उन्हें मिल रही धमकियों से हो रही है। हाल ही में मुंबई के ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर एक धमकी भरा मेसेज मिला है। इसमें अभिनेता सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई के साथ लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी को खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपये की मांग की गई है। मैसेज करने वाले ने लिखा कि इसे हल्के में न लें वरना सलमान खान का हाल भी बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। लॉरेंस से समझौता कराने के बदले रखी ये डिमांड

मुंबई पुलिस के मुताबिक, धमकी भरी मैसेज में लिखा था- इसे हल्के में मत लीजिए। सलमान खान को जिंदा रहना है और उसे लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी है तो उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा।

मुंबई पुलिस मैसेज भेजने वाले को ट्रैक करने में जुटी है। सलमान के करीबी और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सलमान की सुरक्षा बढ़ाई गई थी।

सलमान खान के करीबी और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी बेटे जीशान के दफ्तर के बाहर निकले थे।

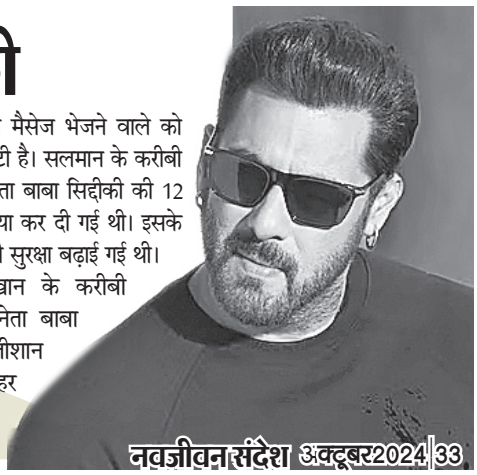

राशिफल

मेष

मेष राशि के जातकों के लिए साल का ग्यारहवां महीना नवंबर मिला-जुला रहने वाला है। माह की शुरुआत में आपको जीवन में अचानक से आने वाली कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण करने की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। यदि आप ऐसा करने में कामयाब रहते हैं तो मनचाहा लाभ हासिल करेंगे।

मिथुन

मिथुन राशि के जातकों को नवंबर माह में किसी भी कार्य में लापरवाही या फिर उसे कल पर टालने से बचना चाहिए, अन्यथा आपके बने-बनाए काम बिगड़ सकते हैं। माह की शुरुआत में आपको धन सोच-समझकर कर खर्च करने की जरूरत रहेगी, अन्यथा आपका बजट गड़बड़ा सकता है। इस दौरान किसी से कोई ऐसा वादा न करें, जिसे आपको भविष्य में निभाने में परेशानी उठानी पड़े।

सिंह

सिंह राशि के जातकों के लिए यह माह बीते माह के मुकाबले अधिक शुभ और सफलता को लिए हुए है। माह की शुरुआत में करिअर-कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद एवं मनचाही सफलता दिलाने वाली साबित होंगी। सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होने पर आपके भीतर गजब का उत्साह बना रहेगा। खास बात यह कि इस माह आपको घर और बाहर दोनों जगह लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा।

तुला

तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर महीने की शुरुआत में अपने समय और धन दोनों को सोच-समझकर खर्च करने की जरूरत रहेगी। इस दौरान अचानक से कुछ बड़े खर्च आने से आपका बजट गड़बड़ा सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अपना काम किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने से बचना चाहिए अन्यथा उसमें होने वाली गलतियों अथवा समय पर काम न पूरा होने के लिए बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है।

धनु

धनु राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना आपदा और अवसर दोनों को साथ लिए हुए है, लेकिन यदि आप चाहें तो अपनी सूझबूझ से हर आपदा को अपने लिए बेहतर अवसर में बदल सकते हैं। माह की शुरुआत में आपको करिअर-कारोबार से जुड़े अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप रोजगार की तलाश में हैं तो आपकी खोज पूरी होगी। वहीं पहले से नौकरी कर रहे लोगों का प्रमोशन या फिर कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है।

कुंभ

कुंभ राशि के जातकों को नवंबर महीने की शुरुआत में करिअर, कारोबार और पढ़ाई-लिखाई में कुछ बाधाओं को सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन पढ़ाई-लिखाई से उचट सकता है तो वहीं नौकरीपेशा लोगों को जाने-अनजाने हुई किसी भूल या लापरवाही के लिए सीनियर के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है।

वृषभ

नवंबर माह की शुरुआत में अचानक से होने वाले बड़े खर्च वृष राशि के जातकों का आर्थिक बजट बिगाड़ सकते हैं। इस दौरान आपको अपने संतान से जुड़ी किसी बात को लेकर मन चिंतित रहेगा। नौकरीपेशा लोगों के सिर पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। इस दौरान आपको करिअर-कारोबार या फिर निजी कारणों के लिए लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करना पड़ सकता है।

कर्क

माह की शुरुआत में नौकरीपेशा लोगों की आय के अतिरक्त आय के स्रोत बनेंगे। व्यवसाय में मनचाहा लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन आय के मुकाबले खर्च की अधिकता बनी रहेगी। इस दौरान मकान की मरम्मत या सुख-सुविधा में अधिक धन खर्च होगा। माह के दूसरे सप्ताह में करिअर-कारोबार में लंबी दूरी की यात्रा संभव है। यात्रा सुखद एवं मनचाही सफलता देने वाली रहेगी।

कन्या

कन्या राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना मिला-जुला रहने वाला है। माह की शुरुआत में नौकरीपेशा लोगों पर काम का अधिक दबाव रहेगा। जिसे समय पर पूरा करने के लिए उन्हें अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना होगा। वही निजी जीवन में कुछ घरेलू समस्याएं आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेगी। इस दौरान परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रहेगा।

वृश्चिक

वृश्चिक राशि के लोगों को इस माह अपनी सेहत और संबंधों पर खूब ध्यान देने की जरूरत रहेगी। माह की शुरुआत में ही मौसमी या फिर किसी पुरानी बीमारी के कारण आपको शारीरिक एवं मानसिक कष्ट सहने पड़ सकते हैं। सेहत संबंधी दिक्कतों की अनदेखी न करें, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। इस दौरान अपनी दिनचर्या और खान-पान का विशेष ध्यान रखें।

मकर

मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कभी खुशी तो कभी गम लिए रहने वाला है। माह की शुरुआत में भूमि-भवन से जुड़े मामले में फैसला आपके हक में आने से आप राहत की सांस लेंगे। यह समय परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए भी बेहद शुभ रहने वाला है। नवंबर महीने की शुरुआत में ही उन्हें उनकी परिश्रम का मनचाहा फल मिल सकता है।

मीन

मीन राशि के जातकों को नवंबर महीने की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में कामकाज की अधिकता बनी रहेगी। इस दौरान आपको अपने टारगेट को समय से पूरा करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करने होंगे। कामकाजी महिलाओं को घर और कार्यक्षेत्र के बीच तालमेल बिठाने में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। भूमि-भवन से जुड़े विवाद में आपको कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।

75 Azadi Ka Amrit Mahotsav
SMILES
TO A MILLION
ENERGY SECURITY
TO A BILLION
Coal India
MCL
Enabling Ease of Living...
MAHANADI COALFIELDS LIMITED
(A Govt. of India Undertaking & Subsidiary of Coal India Limited)
Jagruti Vihar, Burla, Dist: Sambalpur-768020 (Odisha)
www.mahanadicoal.in | @mahanadicoal

Postal Registration No! : RN/262/2023 25

DAMODAR VALLEY CORPORATION

UNDER THE MINISTRY OF POWER (GOVERNMENT OF INDIA)

77 year of service to the Nation

Promoting Industrial Growth in the Valley and Beyond...

@Damodar.Valley.Corporation

@damodarvalleyco

@DamodarVC

@dvc1948

damodar-valley-corporation-dvc

Our Past and Present

Established on 7 July 1948 as the First Multipurpose River Valley Project of Independent India

Harbinger of industrial and socio economic growth spread across 24,235 sq kms in Jharkhand and West Bengal.

DVC supplies reliable 24x7 quality power to consumers in the valley area and to 8 states across India and even beyond borders.

DVC power stations are consistently ranked among the top 10 in the counry (Central Sector)

PLF achieved in FY: 2023-24 was 76.81%, which is much above national average

9.5% Annual Revenue collection growth in FY: 2023-24